नई दिल्ली
रविवार, 29 जून, 2025, मूल्य-15.00
राष्ट्रीय
वर्ष-7 अंक-36 पृष्ठ- 8
RNI: DELHIN / 2018 / 76679
Postal Reg. No. DL(C)-05/1425/2025-27
License To Post Without Pre Payment No. U(C)-164/2025-27
Magazine Post Reg. No. DL(DS)-31/MP/25-26-27

# संडे नवजीवन

Freedom is in Peril, Defend it with all your might Jawaharlal Nehru

यूपी में परतें खुल रहीं 'जीरो टॉलरेंस' के दावे की, चारों ओर उर्स पर रोक से सांप्रदायिक चेहरा सामने 5

क्या हम घिरते जा रहे 'जल बम' के खतरों से 4

कयामत आई, तब...? 8

www.navjivanindia.com | @navjivanindia | www.nationalheraldindia.com | www.qaumiawaz.com

# मतदाता सूची में सुधार या चुनाव की फिक्सिंग

## महाराष्ट्र में गड़बड़ियों पर राहुल गांधी के सवालों के बाद एक बार फिर आयोग की तटस्थता और विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल

हरजिंदर

चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भेजे गए चर्चा के निमंत्रण से विवादों का नया दौर शुरू हो गया है। आयोग यह चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी आपत्तियों पर करना चाहता है। जबकि मतदाता सूची और मतदान के आंकड़ों में भारी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी मतदान के वीडियो के साथ ही मतदाताओं का ऐसा डेटा मांग रही है जिसका मशीनी आकलन हो सके।

इस टकराव ने एक बार फिर आयोग की तटस्थता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के एंपावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट यानी ईगल नाम से बनाए गए आठ सदस्यीय समूह ने आयोग से मिलने से तब तक के लिए इनकार कर दिया है जब तक उन्हें यह डेटा और वीडियो नहीं मिल जाते।

याद रहे कि आयोग ने दिसंबर 2024 में नियमों में बदलाव कर दिया था ताकि यह डेटा और दस्तावेज लोगों को उपलब्ध न हो सकें। फिर 18 जून को उसने एक सर्कुलर के जरिये मतदान केन्द्रों, स्ट्रांगरूम्स और मतगणना केन्द्रों के सीसीटीवी वीडियो नतीजों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर नष्ट करने का फैसला सुना दिया। अपवाद तब हो सकता है जब हाईकोर्ट में चुनाव नतीजों को लेकर कोई याचिका लंबित हो। पहले इन्हें एक साल तक नष्ट न करने का प्रावधान था।

राहुल गांधी ने 21 जून को इसे लेकर एक्स पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी- 'मतदाता सूची? यह मशीन पर आकलन करने वाले फार्मेट में नहीं मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज? कानून बदल कर छुपा लिए गए। मतदान के वीडियो और फोटो? अब उन्हें एक साल के बजाय 45 दिन में ही डिलीट कर दिया जाएगा। जिसे जवाब देने हैं, वह सबूत मिटाने में लगा है।'

राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव इसमें एक और बात जोड़ते हैं, 'लोकतंत्र खुलेपन से चलता है। आयोग ने सीसीटीवी वीडियो संभाल कर रखने का समय एक साल से घटाकर 45 दिन कर दिया। इससे सिर्फ लोगों का शक बढ़ा है और चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास घटा है।'

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा यह आरोप लगाया था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गंभीर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने मतदाता सूची में कुल 40 लाख नाम जोड़ने पर सवाल उठाया। सूची में दरअसल 48 लाख नए नाम जोड़े गए और आठ लाख हटा दिए गए। इसके अलावा 'मतदान के दिन शाम पांच बजे के बाद मतदान में अकथनीय बढ़ोतरी हुई।' शाम पांच बजे तक मतदान का प्रतिशत 58 था जबकि अगले दिन जो आंकड़े मिले, उसमें यह 66 प्रतिशत था।

कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने आयोग को एक चिट्ठी लिखकर इन अनियमितताओं का जिक्र किया, 'हमने डेटा पेश करके यह दिखाया है कि छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले नए मतदाताओं और पड़ने वाले मतों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई... 40 लाख नए मतदात जोड़े गए और 75 लाख ज्यादा वोट पड़े। मतदाताओं की संख्या में 4.3 फीसद और मतदान में 13 फीसद की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रुझान से मेल नहीं खाते।'

राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की आलोचना के सुर को बढ़ा दिया है और 'वोटों की चोरी' का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि 'महाराष्ट्र की मतदाता सूची की ऐसी डिजिटल कॉपी दी जाए जिसका मशीनी आकलन हो सके और मतदान के दिन के वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए जाएं', इसके बाद ही कोई बात हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि बिना बूथ स्तर के फार्म 20 के डेटा और सीसीटीवी वीडियो के कोई भी बात निरर्थक होगी। विपक्ष के लिए इस तरह का डेटा कोई औपचारिकता नहीं है, यह न्यायसंगत ठहराए जाने का आधार है।

बिहार में चलाए जा रहे 'विशेष सघन पुनरीक्षण' से कई नई चिंताएं उभरी हैं। यह वह समय है जब बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। ऐसे में हर घर पहुंच कर मतदाता सूची की समीक्षा बहुत संभव नहीं होगी। लेकिन इस समीक्षा में जो होना है, वह और भी बड़ी चिंता का विषय है

बृहस्पतिवार 26 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मसले को उठाया। उन्होंने राज्य के पूर्बा मेदनीपुर जिले के तटवर्ती नगर दीघा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'आयोग का निशाना अब बंगाल पर है। खासकर बंगाल के लोगों और विस्थापित मजदूरों पर है।' ममता ने कहा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त की योजना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।' वह बिहार की मतदाता सूचियों की विस्तृत पुनःसमीक्षा पर सवाल का जवाब दे रही थीं।

राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर बार-बार चेतावनी दी है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को उन्होंने 'हमारी राष्ट्रीय संस्था पर कब्जा जमाकर औद्योगिक स्तर पर की गई हेराफेरी' बताया था। उनका तर्क था कि मतदाता सूचियां और निगरानी वीडियो कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं, बल्कि जवाबदेही के औजार हैं। 'ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, जब लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा हो, तो ये ताले में बंद कर के रखने के लिए नहीं हैं।' उनका आरोप है कि चुनाव आयोग न सिर्फ उन्हें छुपा रहा है बल्कि 'सबूतों को नष्ट भी कर रहा है'।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने भी यही चिंता व्यक्त की है। 'द वॉयर' में छपे एक बयान में संगठन के सह-संस्थापक जगदीप छोकड़ आयोग के पारदर्शिता के दावों को खोखला बताते हैं। उनका कहना है कि मशीन द्वारा आकलन लायक डेटा न जारी करना आयोग की विश्वसनीयता को कम करता है।

आयोग का सबसे विवादास्पद फैसला चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में बदलाव है। दिसंबर 2024 में किया गया यह बदलाव मतदान केन्द्रों के सीसीटीवी फुटेज लोगों को उपलब्ध कराने पर रोक लगाता है।

आयोग ने इसे वोटर की निजता की रक्षा और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आधार पर उचित ठहराया है जिसमें अदालत ने कहा था कि वोट न डालने वालों की जानकारी को गुप्त रखा जाए। छोकड़ का कहना है कि निजता महत्वपूर्ण है लेकिन यह पारदर्शिता की कीमत पर नहीं हो सकती। वह कहते हैं, 'आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निजता और पारदर्शिता में संतुलन बनाए, निजता को समीक्षा से बचने की ढाल न बनाए।'

महाराष्ट्र का विवाद अब बिहार में एक बड़े संकट के रूप में सामने आता दिख रहा है। आयोग विपक्ष की आपत्तियों पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है और उन्हें राजनीति से प्रेरित बता रहा है जिससे लोगों का अविश्वास और गहराया है।

शेष पेज 2 पर ▸

# नियम-कायदे ठेंगे पर, देखने वाला कोई नहीं

## बजट में कमी, नियामक संबंधी विफलताएं और प्रणालीगत लापरवाही ने घेर रखा है भारतीय विमानन क्षेत्र को

आदित्य आनंद

अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कठघरे में है। इस पर एयरलाइनों को गलत छूट देने और अपने ही नियम-कानूनों को लागू करने में ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। सरकार भी बजट कम करने और डीजीसीए में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने में ढिलाई बरतने की दोषी लगती है। विभिन्न हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द अवैध इमारतों के अतिक्रमण और उनकी ऊंचाई पर लगी रोक में विफलता के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।

2018 और 2023 के बीच डीजीसीए ने लगातार छह निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित कीं, जिनमें एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा उल्लंघनों की एक लंबी सूची थी, जिसके केन्द्र में रखरखाव के फर्जी आंकड़े, अप्रशिक्षित कर्मचारी, अवधि बीत जाने के बावजूद इस्तेमाल हो रहे सुरक्षा उपकरण और बुनियादी विमानन मानदंडों के नियमित उल्लंघन की बातें थीं। लेकिन इतने गंभीर निष्कर्षों के बावजूद न तो किसी एयरलाइन का नाम लिया गया, न कोई जुर्माना हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई व्यवस्थित सुधार अनिवार्य किया गया हो।

2023 के बाद तो डीजीसीए ने पारदर्शिता को पलीता लगाते हुए सुरक्षा ऑडिट प्रकाशित करना बंद किया ही, किसी घटना की रिपोर्ट अपलोड करने की परंपरा भी खत्म कर दी।

### व्यापक विस्तार

विमानन क्षेत्र में आशातीत तेजी से विस्तार हुआ है। 2014 में 66 मिलियन यात्रियों से बढ़कर 2024 में 161 मिलियन यात्री तो हो गए लेकिन क्या यात्री वृद्धि का यह आंकड़ा नियामक क्षमता से भी मेल खाता है! शायद नहीं। बजट में भारी कटौती हुई है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पूंजीगत व्यय महज एक साल में 91 प्रतिशत गिरा है। इससे संवेदनशील पदों पर रिक्तियों की स्थिति गंभीर हो गई, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम में 30 प्रतिशत की कमी शामिल है। इसने डीजीसीए की निगरानी क्षमता पर असर डाला है। संसद में पेश आंकड़े बताते हैं कि 2020 से जनवरी 2025 के बीच, भारतीय घरेलू एयरलाइनों ने 2,461 तकनीकी खराबियों की सूचना दी, जिनमें से आधे से अधिक इंडिगो एयरलाइंस की थीं। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों ने 389 खराबियों की जानकारी दी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गैर-योग्य व्यक्ति को चालक दल में शामिल करने जैसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन भी थे। इनके बावजूद, नियम-कानून को लागू करना कमजोर रहा और बजट में कटौती जारी है। 2023 में तो एक अत्यंत गंभीर उदाहरण सामने आया जब एयर इंडिया को प्रमुख हवाई अड्डों पर अनधिकृत कर्मियों द्वारा हस्ताक्षरित जाली दस्तावेजों और निरीक्षण न किए जाने के बावजूद प्रमुख हवाई अड्डों पर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का दोषी पाया गया। किसी ने एयरलाइनों द्वारा किए जा रहे इस गोरखधंधे और इन पर नियंत्रण में डीजीसीए के विफल रहने की सूचना सार्वजनिक भी की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

विमान यात्रियों की संख्या लगातार बहुत बढ़ रही है लेकिन विमानन बजट में भारी कटौती जारी है। संवेदनशील रिक्तियों की स्थिति गंभीर हो गई, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम में 30 प्रतिशत की कमी शामिल है

पिछले कुछ सालों में सुधार की मांग ने और जोर पकड़ा है। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ और हितधारक ऐसे स्वतंत्र नागरिक विमानन प्राधिकरण (सीएए) बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे वैधानिक स्वायत्तता, प्रवर्तन शक्तियां तो हासिल हों ही, यह राजनीति और उद्योग के असर से मुक्त रहे। ऐसे संरचनात्मक सुधार के बिना, ऑडिट महज दिखावा रह जाएगा, जो भरोसा बहाल करने या भविष्य की त्रासदियों को रोकने में बाधक होगा। सुरक्षा से जुड़े उपायों को लागू करने में पायलटों और उड़ानों से जुड़े लोगों को शामिल करने की सलाह भी दी गई लेकिन अधिकारियों ने उन पर कान ही नहीं दिया।

### उल्लंघनों की भरमार

2020 से 2025 के बीच, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इर्दगिर्द ऊंचाई संबंधी नियमों को धता बताकर किए गए अनधिकृत निर्माण से विमानन सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अंकुश लगाने के कानूनी और प्रसासनिक प्रयास भी हुए। निर्धारित ऊंचाई सीमा से ज्यादा वाली अनेक इमारतें उड़ान भरने और उतरने के दौरान खतरा पैदा करती हैं। विमानन सुरक्षा ऐक्टिविस्ट यशवंत शेनॉय ने 2019 में एक जनहित याचिका दायर करते हुए इस खतरे की ओर ध्यान खींचते हुए बंबई हाईकोर्ट से ऐसी खतरनाक संरचनाएं हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया।

शेष पेज 2 पर ▸

# मतदाता सूची में सुधार...

पेज एक का शेष

प्रवीण चक्रवर्ती इसे मुक्तसर ढंग से बताते हैं, 'चुनाव आयोग निजी कंपनी नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम जनता को स्पष्ट तौर पर आंकड़े बताना है, उलझाऊ बातें बनाना नहीं। अगर सब कुछ साफ है, तो इसे सबूतों के साथ साबित कीजिए।' आईएएस और सेना के अधिकारी रह चुके एमजी देवसहायम दो टूक शब्दों में कहते हैं, 'पूर्ण गोपनीयता चुनाव आयोग का नया ट्रेड मार्क है।'

यह चिंता किसी एक राज्य या एक चुनाव की नहीं है। चुनाव आयोग का बर्ताव यह मौलिक सवाल उठाता है कि उसका काम चुनाव प्रक्रिया की रक्षा है या चुनावी तथ्यों को सार्वजनिक समीक्षा से रोकना।

बिहार में चलाए जा रहे 'विशेष सघन परिशोधन' से कई नई चिंताएं उभरी हैं। वहां अक्तूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं और उससे कुछ ही महीने पहले यह कवायद की जा रही है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर 25 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सच पता लगाएंगे, जबकि यह समय बिहार में मानूसन का होता है।

यह वह समय है जब बिहार के एक बड़े हिस्से के लिए भारी बारिश की नारंगी चेतावनी जारी हो चुकी है। ऐसे में हर घर पहुंच कर मतदाता सूची की समीक्षा बहुत संभव नहीं होगी। लेकिन इस समीक्षा में जो होना है, वह और भी बड़ी चिंता का विषय है।

इसके दिशानिर्देशों के हिसाब से सभी नए अर्जीदाताओं और 2003 के बाद सूची में नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं को भारतीय नागरिकता का हलफनामा देना होगा- जन्म से नागरिक हैं या बाद में बने। उन्हें इसके सबूत भी देने होंगे- कब और कहां जन्म हुआ और माता-पिता के बारे में भी सबूत। देवसहायम कहते हैं, 'यह तो मूल रूप से लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहना है। क्या सीएए और एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है'।

उन लोगों का क्या होगा, जो ये दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? क्या उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे? इसका मतलब होगा बड़े पैमाने पर लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर देना। खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में जहां जन्म और मृत्यु पंजीकरण अभी भी 75 फीसद से कम है।

जगदीप छोकड़ कहते हैं, 'किसी का नाम मतदाता सूची से हटाने का एक नियमबद्ध तरीका है। आप नए नियमों से इसे कैसे दरकिनार कर सकते हैं?' हालांकि इसका मकसद यह बताया गया है कि इसके जरिये मतदाता सूचियों की सफाई होगी, पर शक यह है कि इससे बिहार में भी वहीं हो सकता है, जिस तरह की गड़बड़ियों का मुद्दा कांग्रेस ने महाराष्ट्र को लेकर उठाया था।

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, 'महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई है, वही अब बिहार में दोहराई जाएगी, या ऐसे किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हार रही हो।' आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है, 'बीजेपी का भांडा फूट चुका है... पूरी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता गया।' ■

# नियम-कायदे ठेंगे पर, देखने वाला कोई नहीं

पेज एक का शेष

समस्या का स्तर चौंकाने वाला है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, भारत के हवाई अड्डों पर इमारतों से लेकर मोबाइल टावर तक ऊंचाई मानकों का खुला उल्लंघन करने वाली 1,800 से अधिक बाधाएं हैं। अकेले मुंबई में ही 400 से अधिक ऐसे निर्माण हैं। ये अतिक्रमण न सिर्फ विमानन सुरक्षा से समझौता हैं, बल्कि यात्रियों और चालक दल के जीवन के लिए भी सीधा खतरा पैदा करते हैं।

2017 में डीजीसीए ने ऐसी 49 बाधाएं ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जो 2010 और 2011 के बीच मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में चिह्नित 110 से अधिक संरचनाओं की एक लंबी सूची का हिस्सा थीं। लेकिन इसे लागू करने में कोताही हुई और कई इमारतें अब भी बनी हुई हैं। कुछ इमारत स्वामियों ने कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इससे भी देरी हो रही है।

बंबई हाईकोर्ट ने 2022 में निगरानी बढ़ाते हुए जुलाई में मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को एयरपोर्ट के पास की 48 इमारतों के अनधिकृत हिस्से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद, अगस्त और सितंबर 2022 में प्रभावित इमारतों के निवासियों के साथ विस्तृत सुनवाई की गई, जिनमें फैज सीएचएसएल, ऑलविन अपार्टमेंट सीएचएसएल, फजल हाउस सीएचएसएल, कुर्ला में फरजान अपार्टमेंट सीएचएस, रिजवी नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दो संरचनाएं और सांताक्रूज (पश्चिम) में धीरज हेरिटेज परिसर आदि शामिल थे। कुर्ला के डिप्टी कलेक्टर ने कार्रवाई के तौर पर इन इमारतों से सात कमरे ध्वस्त करने, मोबाइल एंटीना टावरों की ऊंचाई कम करने और इन इमारतों से 19 सिंटेक्स टैंक और पांच से अधिक ओवरहेड पानी के टैंक हटाने की सूचना अदालत को दी।

मार्च 2025 में बंबई हाईकोर्ट ने त्वरित कारवाई की जरूरत दोहराते हुए डीजीसीए को लंबित अपीलों पर फैसले में तेजी के साथ कलेक्टर तथा नगरपालिका अधिकारियों को अवैध संरचनाएं हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने आधी-अधूरी कारवाई के लिए मई 2025 में बिना शर्त माफी मांगी लेकिन बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एमआईएएल के समन्वय में प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2025 में अदालत को बताया कि 'आदेश अनुपालन के तहत' सात संरचनाओं से अवैध हिस्से हटा दिए गए हैं।

फिलहाल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जहां एक जनहित याचिका के जरिये तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिकारियों की लापरवाही ने नागरिक उड्डयन के लिए, खासकर घनी आबादी वाले शहरी केन्द्रों में एक खतरनाक माहौल बना दिया है। अदालत ने इस मुद्दे की गंभीरता को इंगित करते हुए डीजीसीए, एएआई और विभिन्न राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। विमानन विशेषज्ञ चेतावनी देते रहे हैं कि उड़ान पथ में एक भी अवैध संरचना विनाशकारी हो सकती है, खासकर खराब दृश्यता या आपातकालीन स्थितियों में। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन हवाई अड्डों के आसपास बाधा सीमा लेवल (ओएलएस) अनिवार्य बनाता है, लेकिन भारत में इसका प्रवर्तन सबसे खराब रहा है। नगर निगम के अधिकारियों, राज्य सरकारों और विमानन नियामकों के बीच समन्वय की कमी के कारण उल्लंघन धड़ल्ले से जारी है।

## ग्रीनफील्ड सुविधाओं पर भी असर

अपेक्षाकृत नए हवाई अड्डे भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक आधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा है, जो कभी खुली हरित भूमि से घिरा था, लेकिन अब इसमें तेजी से बदलाव दिख रहा है। यह इलाका जो कभी कृषि भूमि और कम ऊंचाई वाले आवासों का बफर जोन होता था, आज शहर के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ही ऊंचे-ऊंचे आवासीय और वाणिज्यिक टावरों से भरा दिखने लगा है। शहरी योजनाकार चेतावनी दे रहे हैं कि जोनिंग नियंत्रण सख्ती से लागू न हुए तो सुरक्षा बफर के साथ डिजाइन किए गए हवाई अड्डों को भी वही चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी जो पुराने हवाई अड्डों के सामने हैं।

## शहर-दर-शहर खिलवाड़

एएआई डेटा के विश्लेषण से हवाई अड्डों के पास निर्माण ऊंचाइयों में व्यापक गड़बड़ियां सामने आती हैं। मसलन, हवाई अड्डे से 4 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई में इमारत की अधिकतम स्वीकृत ऊंचाई केवल 17.87 मीटर है, जबकि विजयवाड़ा में यह 42.14 मीटर है। ऐसी विसंगतियां अहमदाबाद और लखनऊ-पटना तक, हर जगह मौजूद हैं।

यह सब अनुपालन को तो जटिल बनाता ही है, एक समान प्रवर्तन की बात बेमानी हो जाती है। नियामक विफलता और अतिक्रमण के दोहरे संकट तत्काल, प्रणालीगत सुधार की मांग करते हैं। विशेषज्ञ समितियों का गठन करने और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) को मजबूत करने का सरकार का हालिया निर्णय सही दिशा में एक कदम भले हो, लेकिन आवश्यक व्यापक सुधार के लिए नाकाफी है।

### विशेषज्ञों की सिफारिशें

- नियमों को लागू करवाने और जांच प्राधिकरण सहित वैधानिक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र विमानन सुरक्षा निरीक्षण आयोग का गठन।
- जोखिम-आधारित, पूरे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने वाला एकीकृत ऑडिट सिस्टम लागू करना।
- ऑडिट और घटना रिपोर्ट का नियमित रूप से प्रकाशन और प्रवर्तन कार्रवाइयों को पूरी पारदर्शिता के साथ अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाना।
- हवाई अड्डों के आसपास ऊंचाई प्रतिबंध लागू करने में सख्ती, अवैध संरचनाएं तत्काल ध्वस्त कर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना।
- सक्रिय निगरानी तंत्र को सक्षम करने के लिए डीजीसीए की जनशक्ति, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
- अतिक्रमण रोकने और हटाने के लिए विमानन नियामकों, नगर निगमों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना।

अहमदाबाद दुर्घटना ने याद दिलाया है कि जब निगरानी फेल हो जाती है, तो विश्वास टूट जाता है और नतीजे भयावह होते हैं। केवल निर्णायक कार्रवाई, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और सख्त प्रवर्तन के जरिए ही हमारा नागरिक विमानन क्षेत्र जनता का विश्वास बहाल करने और लाखों यात्रियों की सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द अतिक्रमण पर विचार कर रहा है और देश की इस पर कड़ी नजर है। इसका नतीजा न सिर्फ अवैध ढांचों का भाग्य तय करेगा, भारत में विमानन सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत भी कर सकता है - एक ऐसा युग जिसमें नियामक कठोरता और सार्वजनिक जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ■

# नफरत की राजनीति करती है भाजपा

वकील और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में 2015 से मंत्री थे। जब गौतम ने बौद्ध बने 10 हजार लोगों को शपथ दिलाई कि वे कभी भी हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना नहीं करेंगे, तो भाजपा ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद 2022 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संदर्भवश, यह शपथ डॉ. बी.आर. आम्बेडकर ने भी ली थी, लेकिन भाजपा ने इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने के मौके के तौर पर देखा। 2024 में कांग्रेस का दामन थामने से पहले राजेंद्र पाल गौतम न केवल विधानसभा की सदस्यता बल्कि आम आदमी पार्टी को भी छोड़ चुके थे। गौतम बौद्ध ऐक्टिविस्ट रहे हैं और वह 'मिशन जय भीम' के अलावा एनजीओ 'परिवर्तन' चलाते हैं। अब वह कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रभारी हैं। दलित चिंताओं और राजनीति पर **विश्वदीपक** से बातचीत करते हुए गौतम ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ने का फैसला क्यों किया। बातचीत के अंशः

**आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद आपके कांग्रेस में शामिल होने पर बहुतों को आश्चर्य हुआ। ऐसे लोगों को लगता था कि आप भाजपा में जाएंगे। दिल्लीवालों का मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है। फिर आप कांग्रेस में ही क्यों गए?**

इसका जवाब है देश बचाने के लिए।

**क्या यह कुछ नाटकीय नहीं है? लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर देश के समक्ष ऐसा कौन सा खतरा है जिसे कांग्रेस ही सुलझा सकती है?**

सामाजिक न्याय पर खतरा है। इसलिए देश पर खतरा है। देखिए, जब लोग ताकत के साथ जुड़ते हैं, तो पैसे के लिए, सत्ता के लिए जुड़ते हैं। राजनीति में इस प्रवृत्ति की वजह से देश का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे हालात में मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया।

**आपने किसके बीच में अध्ययन किया और क्या नतीजा निकला?**

अध्ययन किया कि कौन सी पार्टी देश के लिए उपयुक्त है। कौन पार्टी देश को आगे ले जा सकती है। कौन पार्टी देशभक्त है। क्षेत्रीय दलों को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनका अस्तित्व बहुत सीमित है। राष्ट्रीय पार्टी ही देश के लिए सोच सकती है और योजनाएं बना सकती है और उन्हें लागू करा सकती है। वही संसद में दबाव बना सकती है। तब दो राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा का तुलनात्मक अध्ययन किया। आज का आधुनिक भारत कांग्रेस का बनाया हुआ है। जवाहर लाल नेहरू ने डॉ. आम्बेडकर वगैरह के सहयोग से जो बुनियाद रखी, उसी पर आधुनिक भारत टिका है।

उदाहरण के लिए शिक्षा को लेते हैं। इन महापुरुषों ने देश निर्माण की दिशा में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। देश गरीब था, फिर भी शिक्षा निशुल्क थी। खासतौर से हमारे समाज के एससी-एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाती थी जिससे लोग पढ़ लिख जाते थे। वे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेते थे। थोड़ा पैसा भी बचा लेते थे जिससे एकाध जोड़ी कपड़े भी सिलवा लेते थे।

अब विरोधाभास देखिए। देश पांच ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहा है लेकिन शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि एससी-एसटी ओबीसी को तो छोड़ दीजिए, समान्य वर्ग के 70 फीसद लोग अच्छी शिक्षा से महरूम हैं। ट्राइबल सब प्लान पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) में बना। इसमें व्यवस्था थी कि ट्राइबल की जनसंख्या के हिसाब से बजट में इतना दिया जाए कि उनका विकास हो सके।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीएसयूज का निर्माण कांग्रेस ने किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने दिया। भूमिहीनों को खेती और रहने के लिए जमीन देने का फैसला भी कांग्रेस शासन के दौरान हुआ। कांग्रेस के दौर में ही उदारीकरण को लागू किया गया जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। बाद में यूपीए के दौरान आरटीआई, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी जैसे कानून बनाए गए।

ये सारी बातें कांग्रेस की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाती हैं। ये सब कानून ऐसे थे जिसके केन्द्र में देश का आम आदमी, गरीब, वंचित, दलित, अछूत तबका था। कांग्रेस ने उनको ताकत प्रदान की। इसके अलावा, कांग्रेस नफरत नहीं फैलाती। भाजपा धर्म और नफरत की राजनीति करती है। इस सबने मुझे कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

**कांग्रेस की आलोचना होती है कि यह सवर्णों की पार्टी है। पार्टी में एससी-एसटी-ओबीसी-माइनॉरिटी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। खासकर आम्बेडकरवादी ऐसा मानते और प्रचारित भी करते हैं। कांग्रेस के दलित नेताओं को 'सरकारी दलित' कहा जाता था। आप खुद आम्बेडकरवादी रहे हैं। आखिर बदला क्या है?**

सब कुछ बदला है। देश की राजनीति बदली है। भाजपा बदली और कांग्रेस भी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देखिए। पिछले दो साल से वह समाज के अलग-अलग वंचित तबकों से मिल रहे हैं। वह कुलियों, बढ़इयों, किसानों, गिग वर्करों, छात्रों, बैंकरों और रेलवे के लोको स्टाफ आदि से मिल रहे हैं। सबका दुख-दर्द समझ रहे हैं। गरीबों के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। उन्होंने चार हजार किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। भाजपाई उन्हें 'शहजादा' कहते थे। वही लोग खुद दस लाख का सूट पहनकर, लाखों का चश्मा लगाकर, 8 हजार करोड़ के प्लेन में दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, महलों में रह रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। यही फर्क है। राहुल गांधी आज के समय में सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। आज की कांग्रेस पुरानी कांग्रेस से अलग है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पकड़ लिया है।

**आप अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और केजरीवाल ने अपने कार्यालय में सिर्फ आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई थी। क्या कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम थी?**

भगतसिंह नास्तिक थे। केजरीवाल के नास्तिक होने की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। अगर केवल एक ही धर्म में पूरी तरह से रम जाओगे और उसी को आगे बढ़ाओगे, तो फिर केजरीवाल और भाजपा में क्या अंतर रह जाएगा? यही करना है, तो फिर भगत सिंह की फोटो क्यों लगा रहे हो? केजरीवाल आम्बेडकर की फोटो लगाते हैं लेकिन एससी-एसटी-अल्पसंख्यकों और दलितों के कल्याण वाली योजनाओं को बंद कर देते हैं। यहां तक कि मेरे द्वारा शुरू की गई योजनाओं- स्कॉलरशिप, दिल्ली एससी-एसटी-ओबीसी-माइनॉरिटीज फाइनेंसियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास आदि को भी रोक दिया।

> जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे लेकर जाना है। ओबीसी-माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हिस्सेदारी-भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दलित समाज को अहसास करना है कि कांग्रेस ने ही दलितों के विकास के लिए योजनाएं बनाईं

**आप एससी डिपार्टमेंट के चीफ हैं। कांग्रेस का संगठन कमजोर माना जाता है। दलित वोट बिखरा है। आप दलितों को कांग्रेस की तरफ कैसे लाएंगे?**

एजेंडा एकदम स्पष्ट है। जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे लेकर जाना है। इसे गांव-गांव, घर-घर तक लेकर जाएंगे। ओबीसी-माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हिस्सेदारी-भागीदारी को सुनिश्चित करना है। देश के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इकाईयों का गठन करना है। दलित समाज को अहसास करना है कि आपका विकास किसके शासनकाल में हुआ। कांग्रेस ने ही दलितों के विकास के लिए योजनाएं बनाईं। हमें राहुल गांधी के मोहब्बत की राजनीति के पैगाम को गली-गली तक पहुंचाना है।

**उत्तर प्रदेश में कम से कम तीन नेता दलितों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। भाजपा और बसपा के अलावा चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव भी दलितों को लुभाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए स्थितियां क्या होंगी?**

मायावती जी बड़ी नेता और अच्छी प्रशासक रही हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन उनका टाइम अब जा चुका है। दलितों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। दलितों के सवालों पर प्रतिबद्ध पार्टी ही उस रिक्तता को भर सकती है। हम उसे करेंगे। जहां तक चंद्रशेखर आजाद की बात है, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। हां, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता लेकिन यह समय बताएगा कि वह कितनी दूर तक चल पाएंगे, उनके पीछे कौन है और कौन उन्हें धन मुहैया करा रहा है। कुछ चीजें आम हैं और कई बाद में सामने आएंगी। अखिलेश यादव के बारे में मेरी सोच अच्छी है। मैंने एक बार उनसे दलित राजनीति और दलितों की चिंताओं पर दो घंटे तक चर्चा की थी। जब विचारों के क्रियान्वयन की बात आती है, वह फिसल जाते हैं। उनमें एक ही समय दो नावों पर सवार होने की आदत है। यह पहले भले ही कारगर रहा हो, अब नहीं है।

**आप भाजपा से कैसे निपटेंगे जो दावा करती है कि उसने जाति जनगणना को स्वीकार कर लिया है, और प्रधानमंत्री जो लोगों को यह याद दिलाते नहीं थकते कि वह ओबीसी से हैं? भाजपा यह भी दावा करती है कि उसने पार्टी में एससी-एसटी और ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है?**

मोदी जी कठपुतली हैं। वह दी गई स्क्रिप्ट पर चलते हैं। किसी और के इशारे पर नाचते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि ओबीसी के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश में भाजपा 20 साल से सत्ता में है। वहां ओबीसी आबादी 56 प्रतिशत है, जबकि ओबीसी आरक्षण केवल 17 प्रतिशत। ओबीसी महासभा विरोध करते-करते थक गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। इन लोगों ने ओबीसी और दलितों के लिए आरक्षित सरकारी 68,000 पदों में से 8,000 पद हड़प लिए हैं। राज्य के ओबीसी-एससी-एसटी के युवा पिछले दो साल से आंदोलन कर रहे हैं, पर 'ओबीसी पीएम' को उनकी पुकार क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है?

**बिहार में दलित वोटों के बारे में एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी इस साल छह बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और कांग्रेस ने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन राज्य में दलित वोट कई अन्य पार्टियों में बंटे हुए बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति क्या है?**

हम बिहार में दलितों के बीच राहुल जी और कांग्रेस दोनों के लिए सकारात्मक संभावनाएं देख सकते हैं। एक बार जब बिहार के लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होगी, हमें विश्वास है कि लोगों को हमारे साथ जुड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारी कोशिश दलितों के हर वर्ग के साथ जुड़ने और उन्हें जिम्मेदारियां देने की है। बहुत काम चल रहा है और हमें यह स्वीकार करना कि अगर कांग्रेस ने यह सब 20 साल पहले किया होता, तो वह सत्ता से कभी बाहर नहीं होती। लेकिन देर आए, दुरुस्त आए। ■

प्रकाशकः **पवन कुमार बंसल**; संपादकः **राजेश झा**; **पवन कुमार बंसल द्वारा दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड,** हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 11002 की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रित। दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और द्वारा आर. सी. मल्होत्रा, दि इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड प्रेस, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

# यूं ही नहीं ईरान से पूर्ण युद्ध को टालता है अमेरिका

**अमेरिकी प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि ईरान से कोई भी लंबा सैन्य टकराव न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक**

अशोक स्वैन

**विजयी प्रदर्शन** तेहरान के डाउनटाउन में ईरान के झंडों और अमेरिका विरोधी नारों के साथ सीजफायर को इजरायल पर जीत के रूप में मनाते लोग।

मध्य-पूर्व पर लंबे समय से अमेरिका-ईरान युद्ध का दुःस्वपन मंडराता रहा है। टैंकर हमलों, हत्याओं, होर्मुज जलडमरूमध्य में गतिरोध या खुफिया ऑपरेशंस की शक्ल में यह बार-बार सच होता दिखा है। जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच युद्धविराम की असहज सहमति बनने से पहले वह दुःस्वप्न हकीकत के काफी करीब पहुंच गया था।

हां, ईरान और इजरायल के बीच यह एक असहज युद्धविराम है जिस पर वाशिंगटन के अत्यधिक दबाव में सहमति बन सकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 'ऐतिहासिक जीत' का दावा किया, जबकि इजरायल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने कहा कि 'इजरायल युद्ध विराम का सम्मान करेगा, लेकिन तभी तक जब तक दूसरा पक्ष इसका सम्मान करता है'।

उधर, ट्रंप को अपने देश में तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर हवाई हमले का आदेश देने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का डेमोक्रेटिक पार्टी की अगुआई में चलाया गया प्रयास भले विफल हो गया, लेकिन यह राजनीतिक नजारा दिखाता है कि अमेरिका एक ऐसे युद्ध के जोखिम को लेकर कितना विभाजित है जो इस क्षेत्र में पीढ़ी के सबसे खतरनाक संघर्ष में बदल सकता है। सवाल उठता है कि वाशिंगटन अपनी बेमिसाल सैन्य ताकत के बावजूद इस टकराव को 'तार्किक नतीजे' यानी सत्ता परिवर्तन या ईरान की सैन्य क्षमता को ध्वस्त किए बिना आखिर पीछे क्यों हट रहा है?

इसका जवाब सत्तर सालों के उलझे हुए इतिहास और इस सबक में छिपा है कि ईरान कभी भी आसानी से जीता या काबू किया जाने वाला दुश्मन नहीं रहा और उसके खिलाफ ऐसी किसी भी कोशिश की कीमत बहुत ज्यादा आंकी जाती रही है। 1953 में सीआईए और एमआई-6 ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग- जो ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे और जिनके सोवियत संघ के पाले में चले जाने की आशंका थी- की सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। शाह को सत्ता में वापस लाने के लिए वाशिंगटन ने ईरान के लोगों में संदेह और आक्रोश के बीज बो दिए।

यह आक्रोश 1979 के अंत में फूट पड़ा जब छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। शाह के पतन के कारण पहले से ही कमजोर हो चुके राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने संकट के बोझ तले अपने कार्यकाल की चरमराहट झेली। एक असफल ऑपरेशन में ईरान के रेगिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर धू-धूकर जले।

इस घटनाक्रम ने अमेरिका की विदेश नीति प्रतिष्ठान को ऐसा जख्म दिया कि उसके बाद से ही वह ईरान के खिलाफ सैन्य प्रयोग के विकल्प को अपनाने को लेकर खासा सतर्क हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान को धमकी दी है, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, अपने प्रॉक्सी के जरिये बमबारी कराई है, लेकिन खुद उसके खिलाफ सैन्य हमले से परहेज किया है। 9/11 के दौरान और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को 'बुराई की धुरी' का हिस्सा करार दिया था। बुश प्रशासन ने अफगानिस्तान और इराक की सत्ता को बड़ी तेजी से उखाड़ फेंका और उनके खेमे के कई कट्टरपंथियों का मानना था कि अगला नंबर तेहरान का होगा। लेकिन इराक के विद्रोह ने पहले ही हजारों अमेरिकियों की जान और ऑपरेशन में अरबों डॉलर लुटा चुके बुश प्रशासन को उन्हीं सलाहकारों ने ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करने को लेकर आगाह किया। एक तो इराक की तुलना में ईरान तीन गुना बड़ा है, पहाड़ों से घिरा है, और वह न केवल अपने सैनिकों के जरिये मोर्चा थामेगा बल्कि लेबनान से लेकर यमन तक उसके वफादार मीलिशिया अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरेंगे।

ओबामा के कार्यकाल में यह गंभीर वास्तविकता और भी साफ हो गई। ईरान द्वारा अपनी परमाणु-संवर्धन क्षमताओं को बढ़ाने की खुफिया रिपोर्टों के बाद भी बराक ओबामा ने बमबारी के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। उनके आलोचकों ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को नासमझी भरा बताया, लेकिन ओबामा के लिए इसके अलावा सैन्य अभियान का ही विकल्प था। सैन्य अभियान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे तो धकेला जा सकता था, लेकिन शायद उसे खत्म करना संभव नहीं था और इसके लिए भी अमेरिका को ईरान के साथ सीधे युद्ध करते हुए अपने सैनिकों को ईरान में उतारना पड़ता।

> कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर हवाई हमले का आदेश देने के लिए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान भले विफल हो गया, लेकिन यह राजनीतिक परिदृश्य बताता है कि अमेरिका ऐसे युद्ध के जोखिम को लेकर कितना विभाजित है

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इसके उलट रुख अपनाया। उन्होंने ईरान के साथ किए गए परमाणु करार को तोड़ दिया, 'अधिकतम दबाव' बनाने वाले प्रतिबंधों को दोगुना कर दिया और ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की 2020 में हत्या जैसे दुस्साहसिक हमले को हरी झंडी दिखाई। ईरान की जवाबी मिसाइल बमबारी झेलने के बाद भी ट्रंप ने तब ईरान के खिलाफ बमबारी अभियान शुरू करने या जमीनी हमले से परहेज किया।

इस बार बेशक ट्रंप सीधे संघर्ष के काफी करीब पहुंच गए, लेकिन वही 'सावधानी' फिर भी हावी रही। अमेरिकी वायुसेना ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, खाड़ी में एक बड़े व्यापक मिसाइल युद्ध को रोकने के लिए ईरानी कमांड नोड्स और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमला किया और इस तरह इजरायल की मदद भर की। अमेरिका ने इस बार भी बड़े जमीनी ऑपरेशन का विकल्प नहीं चुना क्योंकि इससे तेल संकट भड़क सकता था और पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में जा सकती थी। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले से पहले चेतावनी देने के लिए ट्रंप का सार्वजनिक तौर पर तेहरान को 'धन्यवाद' कहना दोनों पक्षों की समझ का संकेत देता है- दरअसल, कोई भी नरक का दरवाजा नहीं खोलना चाहता। ईरान ने फिर दिखाया है कि उसका मुकाबला करना इतना मुश्किल क्यों है। भूगोल और राष्ट्रवाद तो कारक हैं ही, इसके अलावा उसके शस्त्रागार में प्रॉक्सी का अनोखा हथियार भी है। बेशक ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अमेरिकी पारंपरिक सैन्य क्षमता के आगे नहीं टिकती लेकिन लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और अन्य जगहों की मिलिशिया के जरिये ईरान अमेरिका की नाक में दम जरूर कर सकता है। ईरान के साथ पूर्ण युद्ध छिड़ने से खाड़ी के राजशाही इसमें उलझ जाएंगे, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाएगा और इससे तेल की कीमतों में आसमानी उछाल आने का जोखिम है। फिलहाल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुःस्वप्न बना हुआ है। तीन संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद भी कोई यह मानने को तैयार नहीं कि ईरान का कार्यक्रम हमेशा के लिए तबाह हो गया है। तेहरान जमीन के और नीचे सुविधाएं विकसित कर सकता है या फिर वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है- यह ऐसी आशंका है जिससे वाशिंगटन खौफ खाता है।

फिलहाल, एक असहज युद्धविराम जारी है क्योंकि ईरान संकेत दे रहा है कि वह वाशिंगटन के साथ 'मुद्दों को हल करने' को तैयार है और इसके साथ ही वादा कर रहा है कि अगर इजरायल संयम दिखाए तो वह भी ऐसा ही करेगा। पैटर्न जाना-पहचाना है: सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले प्रहार को पहले ही तलवारें लहराकर कुंद कर देना। ईरान के नेता इस खेल में माहिर हैं: दर्द देने और सीधे टकराने की कीमत बढ़ाने के लिहाज से उकसावा तो हो, लेकिन यह उकसावा उसके खिलाफ हमले को वाजिब ठहराने के लिए काफी न हो। अमेरिका ने काफी दर्द सहकर इसे सीखा है।

अगर अमेरिका-ईरान गतिरोध के बारे में इतिहास कुछ सिखाता है, तो वह यह है: किसी सत्ता को उखाड़ फेंकना आनन-फानन में हो सकता है, लेकिन इसके बाद हालात को स्थिर करने में पीढ़ियां बरबाद हो जाती हैं। शाह के पतन से लेकर बंधक संकट तक, बगदाद में विद्रोह से लेकर आज के युद्धविराम तक, वही पैटर्न चल रहा है। अमेरिका ईरान को दंडित कर सकता है, लेकिन उसे हराने की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे जीतकर भी जीत नहीं मिलेगी।

संदेह नहीं कि हाल के हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और अचानक युद्धविराम ने उन सीमाओं को तोड़ दिया है, जो कभी अकल्पनीय था। फिर भी व्हाइट हाउस और पेंटागन में वही कड़वा सच हमला करने या युद्ध विराम की दिशा में बढ़ने का फैसला करता है कि ईरान के साथ युद्ध बेशक अमेरिका की शर्तों पर शुरू हो जाए, लेकिन उसकी शर्तों पर यह खत्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी टकराव तेल टैंकरों के जलने, दूतावासों पर हमले, कीमतों में उछाल और अमेरिकी सैनिकों के ऐसे इलाके में जान गंवाने के साथ खत्म होगा जिसने सदियों के दौरान तमाम साम्राज्यों को घुटने पर ला दिया है। ■

अशोक स्वैन स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं।

# हालात अस्थिर, खाड़ी में चिंता, इंतजार और बेचैनी

**जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रवासी भारतीयों का इंतजार, उनके पास 'देखने', काम पर बने रहने और चिंता के अलावा विकल्प भी क्या है**

रश्मि सहगल

**असुरक्षा** खाड़ी में प्रवासी श्रमिकों की चिंता काम और सुरक्षा को लेकर तो है ही, मूल निवास को लेकर भी कम नहीं है।

मध्य पूर्व में एक पखवारे से जारी युद्ध क्षेत्र के बाशिंदे प्रवासियों के लिए बहुत बड़े आघात जैसा है। वहां काम करने और रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के श्रम बल की रीढ़ हैं। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी और कतर में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रतीकात्मक, लेकिन दुस्साहसिक हमले से उनकी सुरक्षा भावनाओं को भी झटका लगा है। अमेरिका द्वारा घोषित 'युद्ध विराम' के बावजूद हालात अस्थिर हैं और चिंता का स्तर खासा बढ़ा हुआ। अगर हैं भी, तो गिने-चुने लोग ही स्थायी शांति की उम्मीद कर पा रहे हैं। पर्यटकों के वेश में फैले जासूसों को लेकर अफवाहों ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। जासूसी के संदेह में ईरान और कतर में कई भारतीयों की गिरफ्तारी की अपुष्ट रिपोर्टों ने तो प्रवासी समाज की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि ऐसी रिपोर्ट या अफवाहों से अविश्वास का बढ़ सकता है और इससे भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। आंध्र प्रदेश के एक प्रोजेक्ट इंजीनियर कहते हैं, "अगर ईरान कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, तो वह मध्य पूर्व में अन्य अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। इस पड़ोस में युद्धोन्माद चरम पर है।"

ऐसी ही भावना और जमीनी स्तर पर बेचैनी तमाम अन्य लोगों में भी साफ देखी जा सकती है। कुवैत में कार्यरत एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा, "यह किसी जीवित ज्वालामुखी पर बैठने जैसा है, जो किसी भी क्षण फट सकता है। हमारे परिवार बेहद परेशान हैं। मेरे एक सहकर्मी के पिता लगातार आग्रह कर रहे हैं कि वह भारत लौट आए। उनकी परेशानी ठीक है, लेकिन आखिर कोई नौकरी कैसे छोड़ आए। हम घर वापस जाकर करेंगे भी क्या?" भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और जॉर्डन से लगभग 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाल पाने में सफल रहा। लेकिन यह बमुश्किल सतह को खरोंचने जैसा है। अकेले खाड़ी देशों में ही भारतीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या सत्तर से नब्बे लाख के बीच है। सिर्फ यूएई की ही आबादी अस्सी लाख के आसपास है, जिसमें स्थानीय अमीरातियों की संख्या बमुश्किल दस लाख होगी, बाकी तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से ही हैं। सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत तलमीज़ अहमद कहते हैं, "लोगों की आशंकाएं समझी जा सकती हैं। पहले के क्षेत्रीय संघर्ष, मसलन ईरान-इराक युद्ध या 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का दायरा भौगोलिक रूप से सीमित था। 2018-19 में भी, जब टैंकरों पर हमला हुआ, तो आशंका यही थी कि यह बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप लेगा, लेकिन ईरानियों ने रणनीतिक संयम दिखाया और पीछे हट गए।"

हालांकि दुश्मनी समाप्त होने से राहत की भावना तो है, लेकिन प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग शांति स्थापित करने में भारत सरकार की भूमिका से निराश हैं। क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करना भारत के हित में है, खासकर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। इजरायल को भारत के समर्थन का मतलब दशकों पुराने कूटनीतिक प्रयासों पर पानी फिरना और ईरान जैसे पुराने मित्र से दूर होना है। अफसोस की बात है कि स्पष्टता की यह कमी उस बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए अच्छी नहीं है, जो यह मानता है कि विश्व राजनीति में स्वायत्त नीति अपनाना ही भारत के लिए ज्यादा हितकारी होता। उनका मानना है कि नरेन्द्र मोदी इस माहौल में बेहतर और सार्थक भूमिका निभा सकते थे, क्योंकि युद्ध में शामिल सभी देशों से उनके अच्छे संबंध हैं। तो क्या भारत ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने वाली ताकत के तौर पर अपनी स्थिति बनाने का अवसर खो दिया?

> अब यहां तो नौकरियां मिलना आसान है नहीं, ऐसे में भारतीयों को संघर्षरत इलाकों में जाने से रोकना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या भारतीय अधिकारी उनके हितों का ध्यान रखने की दिशा में पर्याप्त कदम उठा रहे हैं!

अहमद का मानना है कि अमेरिका को इसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका कहना है कि एक बार जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, तो ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा विकल्प भी क्या था! क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना जायज़ हो गया और इसने शांति प्रक्रिया जटिल कर दी। वह कहते हैं, "स्पष्ट है कि अमेरिकियों ने इस बारे में थोड़ा ठहरकर नहीं सोचा।" सऊदी अरब और कतर- दोनों ने दोहा में ईरान के हमलों का विरोध किया है और सऊदी अरब कथित तौर पर भविष्य में हस्तक्षेप रोकने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने या तैनात करने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है।

***

2023-24 में भारतीय प्रवासियों ने 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा राशि यहां भेजी, और यह हर साल बढ़ रही है। पिछले दो दशकों से दुबई में रह रहे यूएई के एक भारतीय चावल निर्यातक ने कहा, "यहां काम करने का माहौल भारत से कहीं बेहतर है, लेकिन मौजूदा अनिश्चितता हमारे लिए अच्छी नहीं है।" दुबई में बड़ी संख्या में भारतीयों पास अच्छी-खासी संपत्ति है तथा रहने और काम करने के लिए दुबई जाने वाले अमीर भारतीयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

हालांकि, इजराइल में हालात बिल्कुल अलग हैं। 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद, इजराइल ने फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह भारत से कई हजार निर्माण श्रमिकों की भर्ती की। अनुमान अलग-अलग हैं, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आने वाले ऐसे श्रमिकों की संख्या 11,000 से 18,000 के बीच है।

एक पूर्व भारतीय राजनयिक कहते हैं, "हमास के हमले के बाद स्पष्ट हो गया था कि हालात और बिगड़ेंगे। कथित तौर पर भारतीय कामगारों को इजरायल में फिलिस्तीनियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है और उनकी कार्यअवधि भी ज्यादा है। उन्हें भेजना हमेशा से जोखिम भरा था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा और यूपी सरकारों ने उन्हें वहां जाने को प्रोत्साहित किया और नौकरियों का लालच दिया।

ईरान ने हाइफा, तेल अवीव और यरुशलम में जिस तरह भारी नुकसान पहुंचाया है, उनका भविष्य फ़िलहाल अनिश्चित है। संघर्ष के बीच ऐसी अपुष्ट रिपोर्टें भी आईं कि श्रमिकों के साथ न सिर्फ खराब व्यवहार किया गया, उन्हें बंकरों में शरण लेने से भी रोका गया। हालांकि सच्चाई का पता लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन कुछ वीडियो जरूर वायरल हुए, जिनमें भारतीयों से भारत लौटने के लिए कहा जा रहा।

तेल अवीव में काम करने वाले राजू निषाद कहते हैं कि पिछले कुछ हफ़्ते काफी तकलीफ़देह रहे हैं, लेकिन दुर्व्यवहार की खबरों को वह खारिज करते हैं। वह कहते हैं, "हम भारत की अपेक्षा इजरायल में तीन गुना ज्यादा कमाते हैं।" सैन्य सेंसरशिप के कारण, उनमें से कोई भी इजरायली अधिकारियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है।

हालांकि, इन निर्माण श्रमिकों की वहां से जाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन 300 से ज्यादा छात्रों, देखभाल करने वालों और तकनीशियनों ने भारत लौटने के लिए जॉर्डन या मिस्र के रास्ते जमीनी रास्ते का विकल्प चुना है। फ़िलहाल लगभग 35,000 भारतीय नागरिक इजरायल में रह रहे हैं।

अब यहां तो नौकरियां मिलना आसान है नहीं, ऐसे में भारतीयों को संघर्ष रत इलाक़ों में जाने से रोक पाना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या भारतीय अधिकारी उनके हितों का ध्यान रखने की दिशा में पर्याप्त कदम उठा रहे हैं! ■

# क्या हम 'जल बम' से घिरते जा रहे?

## भले चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दे रहा, भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। आगे क्या करेगा, कहना मुश्किल

पंकज चतुर्वेदी

**पाकिस्तान** प्रायोजित आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी। पाकिस्तान की लगभग 80-90 प्रतिशत खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति बाधित होने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खरीफ की फसल की बुवाई 20 प्रतिशत तक घट गई है और कृषि क्षेत्र को गहरा झटका लगा है। लेकिन इससे एक और खतरा भी पैदा हो गया है और यह भारत के लिए घंटी की तरह है। मई में पहलगाम में पर्यटकों की आतंकी हत्या के बाद तीन दिनों के युद्ध-जैसे हालात में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा था। भारत के बड़े हिस्से में जो बड़ी नदियां बहती हैं, उनका उद्गम चीन है। चिंता यह है कि यदि चीन ने पानी के मामले में भी पाकिस्तान से दोस्ती निभाई, तो क्या भारत पर भी पानी की मार पड़ सकती है?

पहले सिंधु की ही बात। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास सेंग खबाब नाम के ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत में कुछ सफर तय करने के बाद लद्दाख में प्रवेश करती है। इसके बाद यह जम्मू-कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और बाद में अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा, सतलुज का उद्गम स्थल भी तिब्बत में ही है। यहां तिब्बत में राक्षसताल के पास लांगचेन खबाब हिमनद से निकलती है। भारत में इसका प्रवेश हिमाचल प्रदेश में शिपकी-ला दर्रा के पास है जहां से यह पंजाब में प्रवेश कर कर जाती है। अंत में यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है।

भूस्थानिक शोधकर्ता (जियोलॉजिस्ट) और नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाय नित्यानंद ने सेटेलाइट से मिले सतलुज जल प्रवाह के डाटा पर रिसर्च कर बताया है कि सतलुज नदी से भारत में आने वाले पानी की मात्रा पिछले पांच सालों में 75 फीसद से ज्यादा कम हो गई है। मतलब, सतलुज में भारत आने वाले पानी की मात्रा बीते वर्षों में 8,000 गीगालीटर से घटकर 2,000 गीगालीटर ही रह गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि चीन भारत आने वाले पानी को पहले से ही नियंत्रित कर रहा दिखता है। यह जारी रहा, तो पहले तो हमें ही पानी की कमी झेलनी पड़ेगी। ठीक है कि अंततः पाकिस्तान से प्रभावित होगा, लेकिन हमें यह तो सोचना ही होगा कि हम क्या करेंगे?

इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी चीन नियंत्रित तिब्बत में है। वहां इस नदी का नाम यारलुंग त्सांगपो है। चीन भारत के साथ लगती अपनी सीमा के पास ग्रेट बेंड में यारलुंग त्सांगपो पर 60,000 मेगावाट का मेदोंग बांध बना रहा है। एक खतरा यह भी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि नदियों की धारा के साथ छेड़छाड़ की तो उत्तर-पूर्वी राज्यों में या तो अधिक बाढ़ आ सकती है या फिर, उस इलाके को सूखे का सामना करना पड़ सकता है।

वैसे, लगभग दो दशकों तक त्सांगपो-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) में विकास अध्ययन के उपाध्यक्ष नीलांजन घोष-जैसे लोगों का मानना है कि प्रवाह को मोड़ने का कोई भी प्रयास उलटा होगा क्योंकि इससे तलछट के जमाव के कारण ऊपरी धारा में बाढ़ आ जाएगी। तर्क यह है कि यारलुंग त्सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के कुल जल की मात्रा का मात्र 10-15 प्रतिशत ही योगदान देती है, शेष पानी मुख्य रूप से बारिश और सहायक नदियों से आता है। आंकड़ों के बल पर उनका दावा है कि भारत में नदी के प्रवेश के बाद से, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सहायक नदियों से पोषित होकर बड़े पैमाने पर बढ़ती है। लेकिन मूल बात वही है कि अगर पीछे से पानी लगातार कम होता गया या कभी अचानक बहुत ज्यादा हो गया, तो हम कर ही क्या पाएंगे?

चीन के पास सिर्फ यही 'हथियार' नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर जब-तब वितंडा खड़ा करता रहा है। सियांग नदी यहां की जीवन रेखा माना जाती है। यह भी चीन से ही आती है। सियांग नदी का उदभव पश्चिमी तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से दक्षिणपूर्व में स्थित तमलुंग त्सो (झील) से है। तिब्बत में अपने कोई 1,600 किलोमीटर के रास्ते में इसे यरलुंग त्सांगपो कहते हैं। भारत में दाखिल होने के बाद इस नदी को सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। कोई 230 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह लोहित नदी से जुड़ती है। अरुणाचल के पासीघाट से 35 किलोमीटर नीचे उतर कर इसका जुड़ाव दिबांग से होता है। इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र में समा जाती है। चीन अपने यहां यरलुंग त्सांगपो पर बांध बना रहा। इससे भी वही आशंकाएं हैं जो ब्रह्मपुत्र को लेकर हैं। मतलब यह भी है कि चीन से असम ही नहीं, अरुणाचल की तरफ से भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में, नदियों के प्रवाह में गड़बड़ी कर चीन भारत को परेशान करने की साजिशें करता रहे, तो आश्चर्य नहीं।

फोटो: जेटी इकोलेज

चिंता सिंधु नदी जल बंटवारे पर बेशक भारत और पाकिस्तान में तलवारें खिंची हों, इस नदी का उद्गम चीन में है।

> सियांग नदी का उद्भव पश्चिमी तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से दक्षिणपूर्व में स्थित तमलुंग त्सो झील है। तिब्बत में अपने कोई 1,600 किलोमीटर के रास्ते में इसे यरलुंग त्सांगपो कहते हैं। चीन इस पर बांध बना रहा। इससे भी वही आशंकाएं हैं जो ब्रह्मपुत्र को लेकर हैं। मतलब चीन से अरुणाचल की तरफ से भी खतरा बढ़ गया है

यह तो साधारण-सी बात है कि ऊंचाई से आने वाले पानी का नियंत्रण ऊपर के देश के हाथ ही होगा। ऐसे में, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन नदियों पर बड़े बांध बना कर पानी को रोक सकता है, खासकर सूखे मौसम में। इससे भारत के निचले इलाकों, जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम, में पानी की कमी हो सकती है। इससे कृषि, पीने के पानी की उपलब्धता और जलविद्युत परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सिंधु नदी संधि का स्थगन कर भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी तंत्र की नदियों के प्रवाह के आंकड़े साझा करना बंद कर दिया है। चीन और भारत के बीच भी नदियों के जल स्तर और प्रवाह से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने के समझौते हैं। जो हम अभी पाकिस्तान के साथ कर रहे, वही रवैया चीन ने अपनाया, तो मुश्किल होगी।

2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान वह ऐसा कर भी चुका है। तब डेटा न मिलने से भारत के लिए बाढ़ की भविष्यवाणी करना और उससे निपटना मुश्किल हो गया था। भारी बारिश या बांध के पूरा हो जाने पर अगर वह अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ेगा, तो इससे भारत के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। 2000 में तिब्बत में बांध टूटने के कारण पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही हुई थी, जो इसका एक उदाहरण भी है।

दरअसल, तेज प्रवाह के साथ आई जल धाराएं अकेले तबाही ही नहीं लातीं, उनके साथ जीवन की आस भी आती हैं। असम के कई जिले ऐसे ही प्रवाह के साथ आई मिट्टी पर बसे हैं। काजीरंगा जैसे नैसर्गिक उद्यान का अस्तित्व ही ब्रह्मपुत्र और उसमें आई बाढ़ और बाढ़ के साथ बहकर आई मिट्टी से है।

चीन की सीमा में बन रहे बड़े बांध नदियों में गाद और पोषक तत्वों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक सकते हैं। ये गाद निचले इलाकों की कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसकी कमी से कृषि उत्पादकता कम हो सकती है और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। तिब्बत से लेकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालयीन क्षेत्र भीषण भूकंप-संभावित जोन हैं। इस क्षेत्र में बड़े बांधों का निर्माण भूकंप के जोखिम को बढ़ा सकता है और इससे निचले इलाकों में और भी बड़े पैमाने पर आपदा आ सकती है। बांधों और कथित विकास के अन्य कदमों की वजह से जलवायु परिवर्तन अपना रंग दिखा ही रहा है। ■

# बर्बर हत्या में दिखा पंजाब का चेहरा

## मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन के खिलाफ न कोई शिकायत, न एफआईआर, न कोई अदालती आदेश। फिर भी उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई

हरजिंदर

**साढ़े** चार लाख फॉलोवर्स के साथ कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या ने सब का ध्यान पंजाब में चल रही नैतिक दरोगाई की तरफ खींचा है।

इंटरनेट पर कंचन कुमारी की मौजूदगी बोल्ड वीडियो, मुंहफट बातों और ऐसी सामग्री के लिए चर्चा में रहती थी जो सिर्फ वयस्कों के लिए तैयार की जाती थी। भले ही उसकी पोस्ट पर बहुत से लोगों की भंवें तन जाती हों, उसके खिलाफ न तो कभी कोई शिकायत दर्ज कराई गई, न कोई एफआईआर हुई और न कोई अदालती आदेश ही जारी हुआ। दो हफ्ते पहले उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई।

पुलिस का कहना है कि उग्र सोच वाले नैतिकता के ठेकेदार अमृतपाल सिंह मेहरान को उसके वीडियो 'अनैतिक' लगे और उसने यह कांड कर दिया। उसने प्रचार के लिए शूटिंग के बहाने कंचन को बठिंडा आने का लालच दिया था। हत्या के चंद घंटे के भीतर ही वह अमृतसर से दुबई जाने वाले जहाज में बैठा और फरार हो गया। वह धर्म की रक्षा के नाम पर बनाए गए संगठन 'कौम दे राखे' यानी कौम के रक्षक का नेता था जिसका काम पंजाब में नैतिक दरोगाई था। इसकी अपनी दलील थी, अपनी अदालत थी, और यह खुद ही तय करता था कि किसे जीने का हक है, और किसे नहीं। उसके दो सहयोगी जसप्रीत सिंह और निर्मलजीत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन मेहरान फरार है।

उसके बाद जो हुआ वह पंजाब के मौजूदा समाज की असली तस्वीर पेश करता है। जब कंचन का पार्थिव शरीर पोस्ट मार्टम के बाद उसके परिवार को सौंपा गया, तो कोई एंबुलेंस वाला उसे श्मशान ले जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में सहारा जन सेवा नाम का एक संगठन मदद के लिए आया जो अन्य कामों के अलावा लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया का काम भी करता है।

श्मशान में सिर्फ परिवार के तीन लोग ही थे। न आभासी दुनिया का कोई दोस्त ही वहां था और न कोई परिचित संबंधी ही। कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं आया। वे लाखों लोग जो बेसब्री से उसके शार्ट्स और रील्स का इंतजार करते थे, नजर नहीं आए। जिसके लाखों फॉलोवर थे, उसे अकेले ही जाना पड़ा।

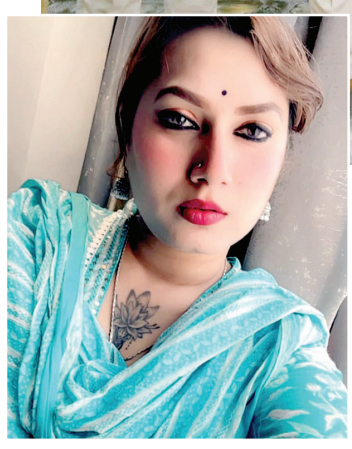

नैतिक दरोगाई पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी निहंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी।

यह सिर्फ एक हत्या की अपराध कथा नहीं है, यह वह आईना है जिसमें आज के पंजाब को देखा जा सकता है। जहां उग्र सोच फैल रही है और इंसाफ की भावना जमीन खो रही है। त्रासदी यह है कि इस हत्या को 'संस्कृति' और 'मूल्यों' के नाम पर जायज ठहराने की कोशिशें भी चल रही हैं।

परेशान करने वाली बात यह है कि फरार मेहरान को धार्मिक, राजनीतिक और डिजिटल कई स्तरों पर समर्थन मिल रहा है। सब घुमा-फिराकर उसे सही ठहराने के लिए कंचन के वीडियो को 'बेहूदा और अनैतिक' बता रहे हैं। इस काम में सबसे आगे रहे स्वर्ण मंदिर के हैड ग्रंथी मलकीत सिंह। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मेहरान की करतूत का समर्थन किया और कहा कि कंचन ने 'सिख नाम का इस्तेमाल करके कौम की छवि खराब करने की कोशिश की।' उन्होंने आगे कहा, 'इसका यही इलाज था, कुछ गलत नहीं हुआ।'

तकरीबन यही बात अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ने भी कही और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव ने भी। फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने तो यहां तक भरोसा दिलाया कि कंचन ने जो 'अपमान' किया है, उस मसले को वह संसद में उठाएंगे।

जैसे इतना ही काफी नहीं था। जल्द ही मेहरान की तस्वीरों वाले बड़े-बड़े कटआउट लुधियाना की सड़कों पर नजर आने लगे। किसी में उसे कौम का हीरा बताया गया और किसी में इज्जत का रक्षक। उग्र सोच वालों को एक नया नायक मिल गया था।

सोशल मीडिया पर यह कथानक कुछ ज्यादा ही स्याह दिखा। हाशिये के उग्रपंथी सोच वालों ने बधाइयों के हैशटैग शुरू कर दिए, जश्न मनाया जाने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब और हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर भी बहते पानी में कूद पड़े। वे हत्या का समर्थन कर रहे थे और 'अनैतिक तत्वों' के चेतावनी दे रहे थे। खुद मेहरान ने भी हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसे जायज ठहराने के दो वीडियो जारी कर दिए। सरहद पार तक से उसे समर्थन मिला। पाकिस्तानी सरगना शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर मेहरान को 'बहादुर शेर' बताया।

मेहरान और उसके साथी खुद को निहंग यानी परंपरागत सिख लड़ाके मानते हैं और वैसा ही बाना भी पहनते हैं। हालांकि वे किसी स्थापित निहंग जत्थेबंदी से जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी जत्थेबंदी है बाबा बुड्ढा दल जिसने इस कृत्य की निंदा की। इसके प्रमुख बाबा बलबीर सिंह ने कहा, 'सच्चा सिख कभी निहत्थों पर हमला नहीं करता, खासकर औरतों पर।'

लेकिन पंजाब के मुख्यधारा के राजनीतिज्ञों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया। राजनीतिक विश्लेषक हरजेश्वर पाल सिंह इस पर कहते हैं, ₹जब इस तरह के उग्रपंथी सोच वाले संगठनों के खिलाफ बोलने का समय आता है, तो राजनीतिज्ञ मौन साध लेते हैं। अगर उनके समर्थन का मौका आए, तो वे पूरी ताकत से साथ खड़े हो जाते हैं।₹

पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने एक बयान में हत्या और नैतिक दरोगाई की निंदा की। लेकिन उसी बयान में आगे यह भी कह दिया कि सामाजिक और नैतिक ताने बाने को कोई चोट न पहुंचे, यह सुनिश्चित करना महिला इन्फ्लुएंसरों की 'पहली जिम्मेदारी' है।

पंजाब सरकार ने इस मामले पर क्या किया? कंचन की हत्या के एक हफ्ते बाद सरकार ने आईटी कानून के तहत 106 इन्फ्लुएंसरों के सोशल मीडिया एकाउंट बंद कर दिए। उन्हें 'आपत्तिजनक' बताया गया। वैसे ये एकाउंट 'आपत्तिजनक' कब हो गए? जाहिर है हत्या के बाद। लेकिन विडंबना यह थी कि हत्या को जायज ठहराने और मेहरान का महिमामंडन करने वाले एकाउंट्स में सरकार को कुछ भी 'आपत्तिजनक' नहीं मिला। यहां यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि सरकार आखिर किसके मूल्यों की रक्षा कर रही है। ■

राज्य 360° • लखनऊ उत्तर प्रदेश

# अब तो अंदर से उधड़ने लगीं 'जीरो टॉलरेंस' की परतें

## विकास और 'चाक-चौबंद' कानून-व्यवस्था के बजते ढिंढोरे के बीच बहुत कुछ ऐसा है कि छुपाए नहीं छुप रहा

फोटो: गेटी इमेजेज

सामने आता सच प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान शोकमग्न श्रद्धालु। अब इसकी पुष्टि हो रही है कि सरकार ने मरने वाले लोगों की संख्या छिपाई।

मिनी बंद्योपाध्याय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार दोहराया है कि उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' है। बार-बार ऐसा बोलकर लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस पर वह अमल भी करते हैं। उनके मंत्री और अफसर भी इसका उल्लेख करना नहीं भूलते। भले ही समाज में विपरीत छवि हो, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन की 'छवि' को लेकर मीडिया में जब-तब खबरें आती रहती हैं।

पर, हाल में हुई कुछ घटनाओं ने इस छवि को खासा धक्का पहुंचाया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री का लोकायुक्त को लिखा एक पत्र हाल में सामने आया जिसमें राज्य के सूचना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच का अनुरोध किया गया है। यह सबसे नया विवाद है जिससे योगी जूझ रहे हैं। यह चिट्ठी ऐसे पत्रकार के यूट्यूब चैनल पर सामने आई जो कभी योगी आदित्यनाथ खेमे के करीबी माने जाते थे। विभाग के एक रिटायर्ड उपनिदेशक ने इस किस्म की अनियमितताओं को सही कहा है जिससे इस पत्र की पुष्टि होती है। विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय के मातहत है, इसलिए भी इसमें भ्रष्टाचार का मसला गरमा गया है। लोकायुक्त जांच का अनुरोध मार्च 2025 में किया गया। हालांकि, इस पर किसी प्रगति की अब तक कोई जानकारी नहीं है। सूचना विभाग पर राज्य और मुख्यमंत्री की छवि बनाने के प्रचार का जिम्मा है। अगस्त 2024 में रिटायर हुए उपनिदेशक की बात मानी जाए, तो विभाग का वार्षिक बजट आठ साल में 3,600 करोड़ हो गया है। सन 2000 में यह 25 करोड़ था। कोई पत्रकार या मीडिया से जुड़ा कोई व्यक्ति विभाग में ऐसी किसी कारगुजारी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रिटायर्ड उपनिदेशक ने आरोप लगाया है कि अखबारों और टीवी के विज्ञापनों तथा प्रचार कार्यक्रमों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए कमीशन लेना-देना सामान्य बात हो चुकी है। उनका कहना है कि इनमें से अधिकतर काम विभाग ने आउटसोर्स कर दिया है और इन सबके बारे में फैसला कुछ खास लोग ही लेते हैं।

### ... वही पत्ते हवा देने लगे

चर्चा का एक अन्य विषय वे आरोप हैं जो कुछ मंत्री अपने ही विभागीय अधिकारियों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर लगा रहे हैं। कम-से-कम चार मंत्रियों ने इसी साल 15 मई से 15 जून के बीच अपने ही विभागों में ट्रांसफर हुए कई अधिकारियों से बातचीत में पाया कि इनके पीछे 'बाहरी तत्वों' का हाथ रहा है। उनलोगों का दावा है कि इन तबादलों में कई सैकड़ा करोड़ के घूस के पैसे इस हाथ से उस हाथ गए हैं। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और स्वास्थ्य, पशुपालन और बेसिक शिक्षा विभागों के मंत्रियों ने इस बारे में खुलकर कहा है। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे 1,000 तबादलों को रद्द करने के साथ इनकी जांच के आदेश भी दिए हैं।

विपक्षी नेताओं ने इस बहाने सरकार पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो कहा है कि 'राज्य में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं।' उन्होंने कहा कि यह पैसा बनाने का रैकेट है और सरकारी विभाग न सिर्फ इच्छा के अनुरूप तबादले बल्कि किसी भी बात के लिए निश्चित कीमत वाले 'बाजार' बन गए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी इस पर चिंता जताई है और इस किस्म के भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच की मांग की है। कड़े शब्दों में जारी बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री से सरकार के इकबाल की रक्षा के लिए 'सख्त' कदम उठाने की सलाह दी है।

अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले एक रिटायर्ड मुख्य सचिव ने इसे 'गंभीर रोग का लक्षण' बताया है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग राज्य में अब पूरी तरह उद्योग है।

### पीछा नहीं छोड़ रहा महाकुंभ का प्रेत

बीबीसी हिन्दी की दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सरकार के लिए एक अलग ही सिरदर्द है। इसमें सरकार के इस दावे को चुनौती दी गई है कि महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी को हुई भगदड़ में सिर्फ 32 श्रद्धालुओं की ही मौत हुई। बीबीसी के पत्रकारों ने भगदड़ में मरे सात राज्यों के कम-से-कम 82 लोगों की पहचान की और उनके परिजनों के घरों तक गए। इनमें से कुछ को 10 से 25 लाख तक के मुआवजे मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें यूपी सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

यह तो हुआ ही, प्रयागराज के प्रमंडलीय आयुक्त ने विभागीय जांच में पाया है कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज और आसपास बनाई गई 42 प्रतिशत सड़कें निर्माण की दृष्टि से कमजोर और मानक से कमतर थीं। जांच में पाया गया कि इस आयोजन के लिए भारी-भरकम बजट था लेकिन 'विकास' के नाम पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, वह पांच माह बाद ही टूटने-ढहने लगा।

भाजपा में भी असंतोष बढ़ रहा है। निजी बातचीत में कुछ विधायकों ने अपनी व्यथा सुनाई जबकि कुछ ने नई दिल्ली के कुछ 'शक्तिशाली लोगों' द्वारा षडयंत्र रचने का संदेह जताया। भ्रष्टाचार बढ़ते जाने की बात अलग भी कर दें, तो उनका कहना था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जिस तरह सूचनाएं मिली हैं, उससे लगता है कि खुफिया एजेंसियों ने भी उनलोगों को कुछ सूचनाएं मुहैया कराईं।

इस डॉक्यूमेंट्री और राज्य सूचना विभाग पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन 'ट्रांसफर गोरखधंधा' और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर घोटाला' खुद सरकार के स्तर पर सामने आया है और योगी के लिए इससे उबरना मुश्किल भरा होगा क्योंकि पंचायत और शहरी निकाय चुनाव नजदीक हैं जबकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ■

मिनी बंद्योपाध्याय दिल्ली की स्वतंत्र पत्रकार हैं।

बीबीसी हिन्दी की दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री में सरकार के इस दावे को चुनौती दी गई है कि महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी को हुई भगदड़ में सिर्फ 32 श्रद्धालुओं की ही मौत हुई। बीबीसी के पत्रकारों ने भगदड़ में मरे सात राज्यों के कम-से-कम 82 लोगों की पहचान की और उनके परिजनों के घरों तक गए

# मेमने को शिकार बनाने से पहले भेड़िये जैसा तर्क

## प्रसिद्ध लोककथा की याद दिलाता है योगी सरकार द्वारा अयोध्या और बाराबंकी में दो परंपरागत सालाना उर्स समारोहों की अनुमति न देना

कृष्ण प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 'कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं' की आड़ में अयोध्या और उसके पड़ोसी बाराबंकी जिले में दो परंपरागत सालाना उर्स समारोहों में एक की अनुमति न देना और दूसरे की अनुमति देकर रद्द कर देना एक प्रसिद्ध लोककथा के भेड़िये के 'तर्क' याद दिलाता है, जो उसने एक निरीह मेमने को शिकार बनाने के बहाने खोजते हुए दिए थे।

लोककथा के अनुसार, एक सुबह प्यासा मेमना जंगल में नदी के निचले बहाव वाले तट पर पानी पी रहा था, तो दूसरे किनारे पर अपना शिकार तलाशते भूखे भेड़िये की नजर में आ गया। जंगल के नियम-कायदों के मुताबिक, वैसे तो भेड़िये के लिए भूख मिटाने के लिए मेमनों की जान ले लेना आम बात थी, लेकिन इस मामले में एक तो भेड़िया थोड़ा 'नैतिक' दिखना चाहता था, दूसरे मेमना इतना असहाय और मासूम था कि भेड़िये को इतने सस्ते में उसकी जान ले लेना ठीक नहीं लगा।

ऐसे में स्वाभाविक ही था कि उसे अपने पक्ष में तर्क की तलाश होती। इसी तलाश में उसने गुस्साते हुए मेमने को घुड़क कर पूछा, 'तेरी हिम्मत कैसे हुई कि नदी का मेरे पीने का पानी पीकर उसे जूठा करे! इसके लिए तू कड़ी सज़ा का हकदार है, और वह सजा मैं तुझे देकर रहूंगा!'

बेचारा मेमना पहले तो कांप उठा, फिर सफाई में बोला, 'गुस्सा मत कीजिए, महाराज! नदी का पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैं उसके निचले तट पर हूं, और आप ऊंचे पर। ऐसे में मैं आपके पीने का पानी जूठा कैसे कर सकता हूं।' बात सही थी, इसलिए भेड़िये ने नया 'तर्क' पेश किया, 'सजा के पात्र तो तुम फिर भी हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने पिछले साल मेरे बारे में झूठ बोला, और मुझे गालियां दी थीं!' बेचारा मेमना! वह तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था! उसने यह बात भेड़िये को बताई तो उसने कहा, 'तब जिसने मुझे गालियां दीं, वह तेरा भाई रहा होगा।' इस पर मेमने का कांपता हुआ-सा जवाब था, 'लेकिन हुजूर, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है।'

अब तक भेड़िये का 'धैर्य' जवाब दे चुका था। वह गुर्राया, 'क्या फर्क पड़ता है इससे! मुझे गालियां देने वाला मेमना जो भी रहा हो, वह, तुम्हारे ही परिवार का तो रहा होगा।' उसने बिना कुछ कहे मेमने को दबोच लिया।

तथ्य यह है कि अयोध्या के खानपुर मसोधा इलाके में स्थित दादा मियां की दरगाह हो जिस पर होने जा रहे उर्स की अनुमति विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई एक शिकायत के बाद रद्द कर दी गई या बाराबंकी में फूलपुर इलाके में सैयद शकील बाबा की दरगाह जिसके उर्स समारोह की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि कुछ ऐसे विवाद सामने आए हैं, जिनसे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। यह बात अलग है कि इन दोनों जगहों पर उर्स के आयोजनों में अशांति या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की एक भी पुरानी नजीर नहीं है।

मेले पर रोक बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह जहां सरकार ने इस बार उर्स की इजाजत नहीं दी है।

### यह अयोध्या है...

वैसे भी सूफी मत की पुरस्कर्ता दरगाहों में किसी भी तरह की धार्मिक या सांप्रदायिक कट्टरता की जगह नहीं होती और 'जो रब है, वही राम है' का प्रचार किया जाता है। अयोध्या के स्वभाव में भी कट्टरता नहीं है। कई पुरानी कब्रों और मजारों पर लगे पत्थर पढ़ें, तो पता चलता है कि कोई ईरान से आकर यहां की मिट्टी का होकर रह गया, तो कोई कहीं और से आकर अपना सूफियाना रंग देते-देते उसी के रंग में रंग गया।

अड़गड़ा स्वर्गद्वार में जिन इब्राहीम शाह का मजार है, उनके बारे में कहा जाता है कि वह ईरान से राजपाट छोड़कर अयोध्या आए और फकीरी में रम गए।

वह ऐसे अकेले शाह भी नहीं हैं। शाह मदार शाह, खजंती शाह, शाह सम्मन फरियाद रथ और शाह फतहल्लाह शाह भी हैं। जानकार बताते हैं कि न इन शाहों को कभी अयोध्या से कोई समस्या हुई, न अयोध्या को उनसे। किसी की भी निगाह में वे आक्रांता या खलनायक नहीं रहे। इस्लाम के पवित्रतम स्थलों में से एक शीश पैगंबर अयोध्या के प्रख्यात मणि पर्वत (जहां से सावन का झूलनोत्सव शुरू होता है) के एकदम पास स्थित है और कोतवाली के बगल स्थित नौगजी कब्र अपने आकार को लेकर आकर्षण का केन्द्र बनी रहती है। कई लोग अयोध्या को 'पैगंबरों की नगरी' या 'खुर्द मक्का' भी कहते हैं। समाजवादी विचार मंच के प्रदेश संयोजक अशोक श्रीवास्तव की मानें, तो अयोध्या की समस्या सिर्फ सांप्रदायिक प्रशासन है। वे बताते हैं कि अयोध्या में प्रशासनों की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों सांप्रदायिकताएं जब भी मौका पाती हैं, गुल खिलाने से बाज नहीं आतीं। इन दिनों तो खैर उनकी मनचाही सरकार है जिसमें उन्हें खुले खेल की छूट मिली हुई है। लेकिन इससे पहले की सरकारों के दौर में भी सांप्रदायिक प्रशासनों ने कुछ कम कारनामे नहीं किए। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या में सरकार जिसकी भी रहे, प्रशासन हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के संगठनों खासकर विश्व हिंदू परिषद का ही रहता आया है।

निस्संदेह, जिन दोनों उर्स का जिक्र किया गया है, उनकी अनुमति से जुड़े फैसलों के वक्त योगी सरकार और उनका जिला प्रशासन इन बातों से अनभिज्ञ नहीं रहा होगा। वह विश्व हिन्दू परिषद भी नहीं जिसने इस प्रबल उम्मीद में दादा मियां की दरगाह के उर्स को लेकर शिकायत की कि उसकी शुभचिंतक सरकार उसकी अनसुनी कर ही नहीं सकती।

इस शिकायत में उसने आरोप लगाया कि दादा मियां का उर्स 'गाजी मियां'( सैयद सालार मसूद गाजी, बहराइच में शताब्दियों से लगते आ रहे जिनके जेठ मेले को इस बार प्रदेश सरकार ने नहीं लगने दिया) के नाम पर आयोजित किया जा रहा था। 'अपनों' की ओर से की गई इस शिकायत को प्रदेश सरकार को आगे बढ़कर लपकना ही था, क्योंकि इससे पहले वह 'आक्रांता, आक्रमणकारी, लुटेरे और हत्यारे' गाजी मियां को खलनायक करार देकर उनकी याद में लगने वाले नेजा मेला (संभल) और बहराइच में उनकी दरगाह के इतिहास-प्रसिद्ध जेठ मेले पर रोक लगा चुकी थी। उक्त मेले पर रोक का आदेश देने वाली वह कोई पहली सत्ता नहीं है।

### जब सिकंदर लोदी ने मेला रोकना चाहा...

सोलहवीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी (1489-1517) ने यह मेला रोकने को कोशिश की, तो उसके 'तर्क' बिल्कुल दूसरे थे-योगी सरकार के तर्कों के सर्वथा विपरीत। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से 2015 में प्रकाशित 'कंक्वेस्ट ऐंड कम्युनिटीः ऑफ्टर लाइफ ऑफ वारियर सेंट गाजी मियां' शीर्षक अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में चर्चित सबाल्टर्न इतिहासकार शाहिद अमीन ने लिखा है कि सिकंदर लोदी इस मेले को रोकने में सफल नहीं हो पाया था क्योंकि आगरा, बनारस और नेपाल तक फैले गाजी मियां के अनुयायियों को रोकना उसके लिए संभव नहीं हुआ था।

### अकबर के दौर में

अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में लिखा है कि बादशाह अकबर ने गाजी मियां की दरगाह के लिए जमीन भी दी थी जिसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने रीइन्फोर्स किया था। उनके बेटे आसफउद्दौला के बारे में कहा जाता है कि वह हर हाल में गाजी मियां के दर पर हाजिरी देते थे। ऐसा कभी नहीं था कि गाज़ी मियां सबके आध्यात्मिक गुरु या सबके लिए आक्रांता ही रहे हों। अलबत्ता, उनके आलोचक भी उनकी निंदा की सीमा तक जाने से परहेज करते रहे हैं। ■

संपादित अंश साभारः thewirehindi.com

उर्स की अनुमति से जुड़े फैसलों के वक्त योगी सरकार और उनका जिला प्रशासन अनभिज्ञ नहीं रहा होगा। वह विश्व हिन्दू परिषद भी नहीं जिसने इस उम्मीद में दादा मियां की दरगाह के उर्स को लेकर शिकायत की कि उसकी शुभचिंतक सरकार अनसुना कर ही नहीं सकती

राज्य 360° तमिलनाडु

# खोदाई से इतिहास का नया अध्याय सामने आया

**तमिलनाडु के सुदूर गांव कीलाडी में हुई एक पुरातात्विक खोज ने इतिहास, पहचान और राजनीति पर एक नया और भीषण संग्राम छेड़ दिया है**

शिव कुमार

तमिलनाडु के इस गुमनाम गांव कीलाडी (तमिल में कीझाडी) के बारे में कम ही लोगों ने सुना होगा। ज्यादातर तमिल भी शायद ही इससे परिचित हों। यह नाम इन दिनों अखबारों की सुर्खियों और राजनीतिक बयानबाजी में छाया हुआ है, और इसका श्रेय के. अमरनाथ रामकृष्ण को जाता है। मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दूर वैगई नदी के तट पर 2014 से 2016 के बीच कीलाडी की खोदाई करने वाली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का नेतृत्व रामकृष्ण ने ही किया था। उन्हें बाद में असम भेज दिया गया।

रामकृष्ण ने संभावित नदी-आधारित सभ्यता की खोज के लिए वैगई तट पर कीलाडी को इसलिए चुना क्योंकि यह क्षेत्र मिट्टी के टीलों से भरा पड़ा है। उनकी सोच सही साबित हुई, क्योंकि नारियल के जिस बाग में खोदाई हुई, वहां बड़ा गुप्त खजाना मिला। यहां ईंट की दीवारें, घुमावदार कुओं जैसी संरचनाएं, चीनी मिट्टी के बर्तन सरीखी कलाकृतियां, लोहे की वस्तुएं और तमिल-ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख सरीखी कीमती धरोहर मिलीं। रामकृष्ण ने खोदाई को लेकर अपने निष्कर्ष 2017 में सार्वजनिक किए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

खोदाई में मिले कुछ शिलालेख सिंधु घाटी की लिपियों से अपने जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं, और संभावना है कि तमिल ब्राह्मी का उद्गम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व (दो पुरातत्वविदों द्वारा दावा किया गया 580 ईसा पूर्व) तक हो सकता है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अशोकन प्राकृत ब्राह्मी से भी प्राचीन होगा। मतलब यह कि स्कूलों-कॉलेजों में अब तक पढ़ाया जाता रहा भारतीय (खासकर दक्षिण भारतीय) इतिहास उलटा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तमिल प्राचीनता की जड़ें और अधिक गहरी दिखाई देंगी। कुछ शिलालेख तो सिंधु घाटी की लिपियों से भी धुंधले ही सही, रिश्ते बताते हैं।

फिलहाल एक ऐसी नई कहानी आकार लेती दिखाई दे रही है, जिसमें हकीकत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्णायक तौर पर यह कहीं नहीं दिखाया गया है कि खोदाई में बर्तनों के टुकड़ों पर मिले शिलालेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कलाकृति जैसी परत से मिलते-जुलते हैं। लेकिन, शायद कीलाडी खोदाई के निष्कर्ष और निहितार्थ एएसआई को अपना अगला कदम बढ़ाने का पर्याप्त आधार दे रहे थे। रामकृष्ण को भाजपा सरकार के कहने पर गुवाहाटी जाने का आदेश मिल गया; कम-से-कम मद्रास विश्वविद्यालय में तमिल के पूर्व प्रोफेसर वी. अरासु सरीखे प्रमुख तमिल समर्थकों का तो ऐसा ही मानना है। हालांकि एएसआई ने इसे महज एक नियमित तबादला बताया। विवाद उस वक्त फिर शुरू हो गया जब इस साल मई में रामकृष्ण ने अपनी 980 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई को भेजी, जिसने इसे खारिज कर दिया। एएसआई ने अपने ही अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट संशोधित करने को कहा। उसके अनुसार तिथि निर्धारण गलत था (580 ईसा पूर्व बहुत जल्दी था) और उसने सुझाव दिया कि इसमें स्ट्रेटीग्राफी (परतकरण) अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि निष्कर्ष जल्दबाजी में निकाले गए थे। रामकृष्ण ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

**खोज** कीलाडी में हुई खोदाई में सामने आए तथ्य एक नई इतिहास-दृष्टि की ओर इशारा कर रहे हैं।

वह अपनी रिपोर्ट पर कायम रहे, जिसके बारे में उनका कहना था कि वह वैज्ञानिक तौर पर व्यापक रूप से स्वीकृत कार्बन डेटिंग और एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एएमएस) का नतीजा थी, और दोनों ही पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारित करने की मान्य विधियां हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइट का उनका पुनर्निर्माण पूरी तरह से स्ट्रेटीग्राफिक तरीकों (पद्धति) और सांस्कृतिक/भौतिक जमा के अनुरूप था। उन्होंने कहा कि कलाकृति भारत के साथ-साथ अमेरिका और इटली में भी परीक्षण के अधीन थी, और उनकी रिपोर्ट उन्हीं निष्कर्षों पर आधारित थी।

एएसआई ने रामकृष्ण की जगह वी. श्रीरामन (तमिलनाडु से ही) को कमान दे दी। श्रीरामन ने पूर्ववर्ती की खोजों पर सवाल उठाया, तो तमिलनाडु सरकार इस मामले को अदालत में ले गई और मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य पुरातत्व विभाग को इस स्थल का प्रभारी बना दिया। अब तक खोदाई में 20,000 से अधिक कलाकृतियां मिल चुकी हैं।

केन्द्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विवाद पर परदा डालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और एएसआई तो महज पहली रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों की पुष्टि करना चाहता है। हालांकि बाद में दिल्ली से रामकृष्ण को नोएडा में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन के निदेशक पद पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इससे अटकलें शांत करने में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, सो नहीं मिली।

हालांकि यह पूरा विवाद महज पुरातात्विक पद्धति या साक्ष्य के बारे में ही हो, ऐसा नहीं है। 'द हिन्दू' के अनुसार, खोदाई और जांच में इस्तेमाल की गई पद्धतियों की वैधता के बारे में टकराव से परे, यह भाजपा के संघ (आरएसएस)-प्रेरित विचारों और द्रविड़ पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के बीच आख्यानों का टकराव ज्यादा है।

इसने भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र और राज्य की डीएमके सरकार के बीच की दूरी भी उजागर कर दी है। तमिल राजनीतिक दल इस प्रकरण में डीएमके के साथ खड़े दिखे और इसे 'तमिलों की विरासत को दबाने' का संघ-प्रेरित प्रयास बताया। पुरातत्व मंत्री थंगम थेन्नारसु की नज़र में यह तमिलों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इसे तमिल गौरव और संस्कृति का अपमान बताते हुए एएसआई द्वारा रामकृष्ण को अपने निष्कर्षों पर फिर से काम करने का आदेश देना तमिल संस्कृति पर एक खुला हमला कहा। उन्होंने भाजपा से पूछा कि क्या उसके पास 'काल्पनिक' सरस्वती सभ्यता के सिद्धांत के समर्थन में कोई साक्ष्य हैं।

## खुलकर सामने आ गई पारिवारिक कलह

तमिलनाडु के सर्वाधिक चर्चित राजनीतिक-सह-व्यावसायिक परिवारों में पिछले कुछ समय से अंदरखाने चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। इसके मुख्य किरदार दिवंगत मुरासोली मारन के बेटे डीएमके सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके बड़े भाई चर्चित मीडिया मुगल और सन टीवी समूह के कर्ता-धर्ता कलानिधि मारन हैं। मुरासोली मारन डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के भतीजे थे।

व्यापक हितों वाली इस लड़ाई के केन्द्र में सन टीवी सरीखे मीडिया साम्राज्य के स्वामित्व का मामला है जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनल, रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म निर्माण और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टीम, सनराइजर्स हैदराबाद शामिल हैं और जिसकी कुल कीमत 11,420 करोड़ रुपये ($1.4 बिलियन) से भी अधिक है। समूह के टीवी चैनल सभी चार दक्षिणी भाषाओं के साथ-साथ मराठी और बंगाली भाषाओं में भी फैले हुए हैं। 2015 में इसे बेचने से पहले स्पाइसजेट में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी थी।

दयानिधि ने कलानिधि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सन टीवी के 60 फीसदी शेयर उस वक्त (15 सितंबर 2003 को) धोखाधड़ी से हथिया लिए जब मुरासोली मारन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। जून 2025 में दायर मुकदमे के अनुसार, कलानिधि ने शेयरधारक और बोर्ड की मंजूरी दरकिनार करते हुए अंकित मूल्य पर 1.2 मिलियन शेयर खुद को हस्तांतरित कर लिए।

कलानिधि ने अपना टेलीविजन चैनल 1990 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया, जब वह अमेरिका से एमबीए की डिग्री लेकर लौटे। कलानिधि का यह प्रयोग सफल रहा, उनके चैनल बहुत जल्द लोकप्रिय हो गए और 2006 में सन टीवी सार्वजनिक हो गया, जिसने उन्हें रातों-रात अरबपति बना दिया।

समूह की अपार सफलता के साथ ही किसके हाथ में क्या जैसी चर्चाएं शुरू हुईं और भाइयों के मतभेद की खबरें खुलने लगीं, जिन्हें तब कथित तौर पर उनके चाचा, मुरासोली सेल्वम, मुरासोली मारन के भाई और करुणानिधि ने मिलकर सुलझा लिया था।

10 जून को दायर मुकदमे के अनुसार, कलानिधि ने सन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के 1.2 मिलियन शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के नाममात्र अंकित मूल्य पर "धोखाधड़ी से" अपने नाम कर लिए, जबकि वास्तविक मूल्य 2,500-3,000 रुपये के बीच था। इससे कंपनी का 60 प्रतिशत नियंत्रण कलानिधि के हाथ में चला गया, जो मारन और करुणानिधि परिवारों के बीच 50:50 की साझेदारी का उल्लंघन था। दयानिधि ने अब 15 सितंबर से पहले की स्थिति बहाल करने, लाभांश की वापसी और ईडी, एसएफआईओ और सेबी द्वारा जांच की मांग की है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की खरीद सहित अन्य उपक्रमों के वित्तपोषण में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया है।

हालांकि सन टीवी ने आरोप निराधार और व्यक्तिगत बताते हुए खारिज कर दिया है, लेकिन इस सब के राजनीतिक निहितार्थ निकलने ही हैं। इसमें एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के वारिस, मसलन मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके भाई अलागिरी, तमिलारासु और बहन सेल्वी शामिल हैं। स्टालिन अब तक इस मामले में चुप दिखे, लेकिन खबरें हैं कि उन्होंने मध्यस्थता का प्रयास किया तो था, दयानिधि राजी नहीं हुए। स्टालिन का रुख मारन भाइयों के साथ रिश्तों में उस गर्मी की कमी भी दिखाता है, जैसी उनके पिताओं के बीच के दिखती थी।

पर्यवेक्षक इसे राजनीतिक बिगाड़ से ज्यादा कॉरपोरेट अदावत के तौर पर देखते हैं। फिर भी, चुनाव नजदीक होने और कीलाडी विवाद के कारण पहले से ही भड़की तमिल भवनाओं के साथ, डीएमके नेतृत्व सधे कदम चल रहा है। ऐसे राज्य में जहां परिवार, मीडिया और राजनीति आपस में गहरे जुड़े हों, ऐसी लड़ाइयों का लंबे समय तक निजी रह पाना आसान नहीं होता। ■

---

# इजरायल-ईरान और गाजा पर दिखावा ही

**हम उन चर्चाओं से भागते हैं जिन्हें प्रभावित कर सकते हैं। उन सम्मेलनों में हंसी-ठिठोली करते हैं जिनमें महज दर्शक होते हैं**

आकार पटेल

इसी महीने सरकार ने ऐलान किया कि भारत ने ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज को विश्व मंच पर लाने की जिम्मेदारी ली है। जैसा कि एक अखबार की हेडलाइन में लिखा गया है: 'मौजूदगी का अहसास कराने का वक्त, वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की आवाज़: जी7 से पहले एस. जयशंकर'।

संयोगवश, भारत बीते तीन साल से वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वैश्विक दक्षिण की आवाज पर शिखर सम्मेलन) की मेजबानी कर रहा है जिसे सरकार ने लघु संज्ञा में वीओजीएसएस कर दिया है।

हमारी जिम्मेदारी की घोषणा करने के लिए फौरी वजह जी-7 में हमारा जाना था जिसका भारत सदस्य ही नहीं है। अलबत्ता मैक्सिको, ब्राजील, कोमोरोस और कुक आइलैंड्स जैसे अन्य देशों के साथ-साथ पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया गया है, यानी महज एक दर्शक भर। भारत की कोई वास्तविक भूमिका नहीं है। हालांकि कभी-कभी गले मिलना और हंसी-मजाक करने की इजाजत मिल जाती है।

जी-7 दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का संगठन है। जी-7 ने बयान जारी कर इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की। बयान में उस बमबारी का जिक्र करते हुए इजरायल की सुरक्षा का समर्थन करने की बात दोहराई गई जिसमें तेहरान और अन्य जगहों पर वैज्ञानिकों और नागरिकों की मौत हुई है। इस बयान में जोर देकर कहा गया कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ईरान इस क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है।

इस बयान पर वीओजीएस का कोई मत नहीं है, भले ही हमारे प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को निहारा भर और यह कि 'हमारी मौजूदगी का एहसास कराने का समय है', कहने के बावजूद वीओजीएस मौन ही रहा। यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर हम ऐसे सम्मेलनों या बैठकों में जाते ही क्यों हैं जहां हमारी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन फिर ताकतवर शक्तियों से कौन सवाल कर सकता है? उनके पास अपने कारण हैं। हकीकत तो यह है कि यह समय था कि हम अपनी उपस्थिति को कहीं और महसूस कराएं।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) - जिसका वीओजीएस सदस्य है और वास्तव में इसमें अपनी बात रखता है - उसने भी इसी बाबत बयान जारी किया। एससीओ में नौ देश हैं: चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन नौ देशों की आबादी दुनिया की आबाद की करीब 42 फीसद है, यानी वैश्विक दक्षिण का बहुमत है। एससीओ का चार्टर कहता है कि इसका काम 'एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना' है। इसका मतलब है कि यह कमजोर और गरीब देशों के अधिकारों के लिए खड़ा होगा।

एससीओ ने बयान जारी कर 'इजरायल द्वारा किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा की' और कहा कि 'नागरिकों को निशाना बनाने वाली, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं पर ऐसी आक्रामक कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हैं।' इसी दिन (14 जून को शनिवार के दिन) भारत ने एक जवाबी बयान जारी कर एससीओ द्वारा जारी किए गए बयान से खुद को अलग कर लिया है और स्पष्ट किया कि, 'भारत एससीओ द्वारा उल्लिखित बयान को लेकर की गई चर्चा में शामिल नहीं हुआ था।'

इस तरह देखें तो फिर सामने आता है कि हम ऐसी चर्चा से भी भाग खड़े हुए जहां हम एक भागीदार होने के नाते अपनी बात रख सकते थे, बजाए इसके हम सिर्फ एक मूक दर्शक बन कर रह गए। वैसे भी वीओजीएस काफी रहस्यात्मक तरीके से काम करता है।

14 जून के एक अखबार में एक हेडलाइन थी, 'गाजा के साथ युद्ध विराम के लिए लाए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से भारत ने किनारा किया, 149 देशों ने समर्थन किया'। इस प्रस्ताव में 'भुखमरी और जरूरी मदद से इनकार करने को युद्ध की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल' करने की निंदा की गई थी और इजरायल से गाजा के लिए जाने वाली मदद के रास्ते में लगाए गए अवरोध हटाने की मांग की गई थी। सभी दक्षिण एशियाई देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जबकि वीओजीएस इससे दूर रहा।

इसका कारण यह बताया गया: 'भारत का इस बात पर विश्वास था कि विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है' और 'हमारा संयुक्त प्रयास दोनों पक्षों को करीब लाने की दिशा में होना चाहिए'। निश्चित ही ऐसा होना चाहिए, हमें हमलावर और हमले के शिकार देशों को साथ लाना ही चाहिए। इससे क्रिकेट की वह बात याद आती है जिसमें कुछ भी न करने को अहमियत देने को 'शोल्डरिंग आर्म्स' यानी कंधे पर हाथ रखना कहा जाता है।

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत ने 14 अगस्त 2024 को तीसरे वीओजीएस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें कहा गया है, 'यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई, और यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। इसमें वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है।'

8 मई को रोहिंग्या शरणार्थियों के हालात और निर्वासन से संबंधित एक मामले में उसी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह न तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड को मान्यता देती है और न ही रोहिंग्याओं को शरणार्थी के रूप में मान्यता देती है क्योंकि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए वह शरणार्थियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। जाहिर है कि वीओजीएस और वैश्विक परिवार के बारे में इसकी शेखी बघारने के साथ कई नियम और शर्तें जुड़ी हुई हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का समर्थन न करना लोगों को खतरे, उत्पीड़न और बिन देश का व्यक्ति बनाने की स्थिति में धकेलने का बहाना नहीं हो सकता। प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून में 'गैर-वापसी' के सिद्धांत के तहत, भारत को अभी भी लोगों को उन जगहों पर वापस जाने के लिए मजबूर करने से बचना चाहिए जहां उन्हें गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के तहत एक विशिष्ट कानूनी दायित्व भी है जिसमें भारत भी एक पक्ष है।

लेकिन हम आखिर क्यों परवाह करें? और हमें वैश्विक दक्षिण और हमारी साझा मानवता के बारे में बड़े-बड़े भाषण देने से कौन ही रोक रहा है, जबकि हम इसके बिलकुल विपरीत तरीके से काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, और इसलिए यह दिखावा जारी रहेगा। ■

**महज दर्शक** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कनाडा में हुए जी7 सम्मेलन में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए जिसमें भारत की कोई वास्तविक भूमिका नहीं है।

> हम आखिर क्यों परवाह करें? और हमें वैश्विक दक्षिण और हमारी साझा मानवता के बारे में बड़े-बड़े भाषण देने से कौन ही रोक रहा है, जबकि हम इसके बिलकुल विपरीत तरीके से काम कर रहे हैं?

# ट्रंप बनाम मोदी किसका झूठ सबसे मजबूत?

**हो न हो, सभी तरफ से कुछ न कुछ झूठ बोला जा रहा है। पूरे सच के लिए इतिहासकारों पर निर्भर होना पड़ेगा**

योगेन्द्र यादव

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा करना मुश्किल है। सच से उनका छत्तीस का आंकड़ा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 बार झूठ बोला था, यानी प्रतिदिन 21 झूठ। उन्हें जानने वाले लोग कहते हैं कि उनका सारा जीवन असत्य के प्रयोग करते हुए बीता है। अपने मां-बाप की पैदाइश से लेकर अपने बिजनेस और महिलाओं से संबंध से लेकर राजनीति — कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर ट्रंप का झूठ पकड़ा न जा चुका हो। झूठ पकड़े जाने से उन पर उतना ही असर होता है जितना चिकने घड़े पर पानी का। इसलिए जब डॉनल्ड ट्रंप यह दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में युद्ध को एटम बम वाली खतरनाक दिशा में जाने से रोक दिया, तो उसे उतनी गंभीरता से भी नहीं लिया जा सकता जैसे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बयान को लिया जाना चाहिए।

इधर, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हैं। वैसे, उनके झूठ की कभी गिनती नहीं हुई है (हमारे किस अखबार की मजाल!), अगर होती भी, तो ट्रंप से कम ही निकलती। ट्रंप ने तो मानो सच न बोलने की कसम खा रखी है। मोदी जी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। वह इस मामले में परिस्थिति सापेक्ष हैं — न सच से दोस्ती, न ही सच से बैर। जहां सच से काम चल गया, वहां सच। लेकिन जरूरत पड़े, तो असत्य से भी परहेज नहीं है उन्हें। चाहे हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख डालने का वादा हो या फिर किसान की आय दुगनी करने का। नोटबंदी से देश को हुए फायदे का दावा हो या कोविड के दौरान हुई मौतों की संख्या का। या फिर लद्दाख में "कोई नहीं घुसा है" जैसे बयान हों। इस इतिहास के चलते उनके किसी बयान को भी स्वयंसिद्ध नहीं माना जा सकता।

इसलिए भारत-पाकिस्तान युद्धविराम कैसे हुआ, किसने करवाया और किस शर्त पर इस मसले पर किसी एक नेता के बयान को आंख मूंदकर मान लेने की बजाय तथ्यों की जांच करना जरूरी होगा। पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर एक बड़ा मोड़ आया जब जी-7 की कनाडा में हुई बैठक से ट्रंप को जल्दी निकलना पड़ा और दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, तब कनाडा से ही प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को कोई 35 मिनट तक टेलीफोन कॉल हुई। इस वार्ता के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बातचीत का ब्यौरा देते हुए एक बयान आया। इस बयान में पहली बार भारत सरकार ने ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान में मध्यस्थता करवाने के दावे का खंडन किया गया। इस बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ तौर पर बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते या भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के किसी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई बंद करने की चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सशस्त्र बलों के बीच मौजूदा संचार चैनलों के जरिये सीधे हुई और इसकी शुरुआत पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा कि भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और कभी नहीं करेगा। इस मामले पर भारत में पूरी तरह से राजनीतिक सहमति है।"

राम मिलाए जोड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को मान लिया? भारत सरकार का बयान इस पर चुप है। अमेरिकी पक्ष से इस टेलीफोन कॉल के बारे में कोई बयान जारी नहीं हुआ। भारतीय बयान सिर्फ इतना कहता है कि ट्रंप ने मोदी की बात को ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने का क्या असर हुआ, इसके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस बातचीत के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने यह दावा तेरहवीं बार दोहराया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया था। वार्ता के अगले दिन ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मुनीर को लंच पर बुलाया, जहां मुनीर ने ट्रंप के इस दावे की पुष्टि की और उन्हें युद्धविराम के लिए धन्यवाद दिया। मतलब ढाक के तीन पात।

फिर भी भारत सरकार का बयान महत्वहीन नहीं है। मोदी जी ने ट्रंप को क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, इसे छोड़कर इस बयान में एक अच्छी बात है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भारत-पाकिस्तान संबंध में अमेरिका की मध्यस्थता भारत में किसी पक्ष को भी नहीं चाहिए। पिछले छह दशक से भारत की तमाम सरकारों में इस बात पर सहमति रही है। यानी कि इतना तो आश्वस्त हो सकते हैं कि इस प्रकरण में जो भी हुआ, भारत आगे से अपनी विदेश नीति के इस संकल्प पर कायम रहेगा।

लेकिन यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम किसने करवाया, किन शर्तों पर हुआ। मोदी-ट्रंप फोन कॉल के बारे में जारी भारतीय बयान इस बात को तो स्वीकार करता है कि युद्धविराम से 24 घंटे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैन्स ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, युद्ध के बारे में बातचीत की थी।

मोदी जी ने फोन पर यह तो कहा कि उस दौरान कहीं व्यापार की बात नहीं हुई, लेकिन यह नहीं बताया कि और क्या कुछ बात हुई। बयान इसकी सफाई नहीं देता कि अगर युद्धविराम की बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, तो युद्धविराम की घोषणा भारत या पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बजाय सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे कर दी? मोदी जी ने यह बताया कि युद्धविराम की पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई। यह बात सही लगती है, चूंकि तीसरे दिन की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान की वायु सेना को भारी नुकसान की खबर है। लेकिन मोदी जी ने यह साफ नहीं किया कि क्या पाकिस्तान का अनुरोध अमेरिका के जरिये आया था? मतलब, क्या बातचीत की शुरुआत अमेरिका ने करवाई थी? यह बयान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र ने नाम संदेश में किए उस बड़े दावे पर भी चुप्पी साध जाता है कि युद्धविराम तभी हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से वादा किया गया कि "उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा"। देश को आज तक इन सवालों के उत्तर का इंतजार है: किसने यह वादा किया? किसको किया? इसे लागू कैसे करवाया जाएगा?

ले-देकर अभी भी दाल में कुछ काला नजर आता है। हो न हो, सभी तरफ से कुछ न कुछ झूठ बोला जा रहा है। कहना मुश्किल है कि किसका झूठ सबसे मजबूत। पूरे सच के लिए हमें इतिहासकारों पर निर्भर करना पड़ेगा। ■

**हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हैं। वैसे, उनके झूठ की कभी गिनती नहीं हुई है। अगर होती भी, तो ट्रंप से कम ही निकलती। ट्रंप ने तो मानो सच न बोलने की कसम खा रखी है। मोदी जी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है**

साभार: नवोदय टाइम्स

# भारतीय जीवन यथार्थ के कथाकार अमरकान्त

**1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सीधी भागीदारी से लेकर आमजन के संघर्ष को अपनी रचनाशीलता में आजीवन स्वर देते रहे अमरकान्त का 1 जुलाई से शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है**

पल्लव

अमरकान्त (1 जुलाई 1925 - 17 फरवरी 2014) स्वातंत्र्योत्तर भारत के उन महान लेखकों में अग्रगण्य हैं जिन्होंने कथा साहित्य में अपने समय और समाज को मुखरता के साथ चित्रित किया। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकारों में अमरकान्त का नाम लिया जाता है। अमरकान्त और भीष्म साहनी जैसे कथाकार नई कहानी का एक ऐसा कैनवास बनाते हैं जिसमें देश के मामूली लोगों की जिंदगी और उनके संघर्ष सबसे प्रमुख हैं। इन कहानीकारों ने भारत की बहुसंख्यक जनता की आशा-निराशा और हर्ष-विषाद का चित्रण अपनी कहानियों में बेहद प्राणवान ढंग से किया है कि अपने लिखे जाने के बरसों बाद भी इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठकों को अपना समय और समाज दिखाई देता है।

अमरकान्त ने इलाहाबाद में रहते हुए प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियों में जाना शुरू किया और यही से उनके कहानी लेखन की भी शुरुआत हुई। यह ठीक है कि किसी आकस्मिक घटना या प्रेरणा से कभी कभी कोई व्यक्ति रचनाशील हो जाता है लेकिन उसे सच्चा रचनाकार बनाने के लिए दृष्टि और साधना की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दृष्टि जिसमें व्यापक मनुष्यता के लिए स्थान हो और साधना वह जो लेखक को कला की कसौटी पर भी खरा सिद्ध करे। अमरकान्त का जीवन और लेखन इसका गौरवशाली उदाहरण है। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन जिया और युवावस्था में शुरू हुआ उनका लेखन जीवन के अंतिम समय तक चलता है। लगभग नब्बे वर्ष की आयु में वह दिवंगत हुए तब तक उनके ग्यारह उपन्यासों और लगभग सवा सौ कहानियों का प्रकाशन हो चुका था। उन्होंने बच्चों और प्रौढ़ साक्षरता के लिए भी महत्वपूर्ण लेखन किया।

अमरकान्त का अवदान कहानी साहित्य के लिए कहीं बड़ा, अधिक और मौलिक है। उनकी जिन कहानियों को सादा और शिल्पहीन समझा गया, असल में वे कारीगर की ऐसी कृतियां हैं जिनमें बुनावट के निशान नहीं दिखाई देते। वे सामान्य बोलचाल के लहजे और रोजमर्रा के मुहावरों से अपने समय और समाज की वास्तविक विडंबनाओं को दर्ज करते हैं। वे जीवन के असली, खुरदुरे और कठोर सत्य से भिड़ने की कला संभव करते हैं जब पैंतालीस साल का आदमी अधेड़ बूढ़े में बदल गया है और उसकी पत्नी भय से ग्रस्त है। इस व्याधि का कारण भूख है, बेरोजगारी है, निर्धनता है। आकस्मिक नहीं कि उनके दूसरे ही कहानी संग्रह का शीर्षक 'देश के लोग' है। वे देशप्रेम की वायवीय रोमानियत में नारे लगाने वाली कहानियां नहीं लिख रहे थे बल्कि अभी अभी आजाद हुए और तरक्की का शोर मचाते राजनेताओं को अपने लोगों का हाल बता रहे थे। सामान्य बोलचाल की भाषा होने पर भी अमरकान्त के लेखन में उत्तर भारत की बोलियों के सैकड़ों मुहावरे और हजारों कहावतें हैं, व्यंग्य उनका अचूक हथियार है और वे पात्रों के स्थान पर परिस्थितियों को पैदा करने वाले कारणों पर क्षोभ करते हैं।

कहा जाता है कि अमरकान्त प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। देखा जाए तो भारत का कौन कथाकार होगा जो इस परंपरा में नहीं है?

प्रेमचंद ने कहानी और लेखन के जो मैयार तय कर दिए, उनके पार जाना इसलिए संभव नहीं है कि उन्होंने भारतीय समाज के लिए साहित्य का वास्तविक आशय स्थापित किया था। उन्होंने बताया था कि हमारे साहित्य के नायक कौन हो सकते हैं और क्यों। उन्होंने इस साहित्य के उद्देश्यों को फिर परिभाषित कर दिया था जहां किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, वे भारत महादेश की दो सबसे बड़ी भाषाओं के साझे कथाकार थे और दो संस्कृतियों के साझीदार भी। अमरकान्त इस काम को आगे बढ़ाते हैं और अपने देश के उन लाखों विपन्न, वंचित और पीड़ित लोगों का जीवन शब्दों में दर्ज करते हैं। वे इन लोगों से पाठकों को प्रेम करना सिखाते हैं। वे बताते हैं कि रजुआ जैसे गंदगी में पड़े लोग भी हमारे देशवासी हैं और उनसे नफरत करने से देश को कुछ हासिल नहीं होगा। वे जाति से मुंह नहीं छिपाते और उनके पात्र जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपनी जाति की घोषणा करते हैं क्योंकि अमरकान्त को मालूम है कि भारतीय समाज में जाति एक बड़ी सचाई है।

भूख उनकी कहानियों में बार बार आने वाला विषय है जिससे मालूम होता है कि अमरकान्त की दृष्टि कितनी जमीनी और यथार्थपरक है। वेल्टहंगरहिल्फ़ द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक (जी.एच.आई.) 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भूख के मामले में भारत की स्थिति विशेष रूप से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से तुलनात्मक रूप में चिंताजनक है, जो भुखमरी के स्तर के मामले में "मध्यम" श्रेणी में आते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है, जबकि पांच साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन से ग्रसित हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भूख और गरीबी भारत के लाखों नागरिकों के लिए आज भी सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है। क्या हम अन्न के उत्पादन में पीछे रह गए हैं? यहीं भारत सरकार की सूचना है कि एफएओ (2023) के अनुसार भारत दुनिया में अनाज उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। फिर समस्या कहां है? क्या यह समाज में बढ़ती गैर बराबरी के कारण हो रहा है?

यहां यह तथ्य भी हमारे सामने है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात् प्रति माह प्रति एएवाई परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न) दिनांक 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय लिया है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अमरकान्त की कहानियां भूख के सवाल को बार बार उठाती हैं तो यह एक जरूरी काम है जो किसी भी देशप्रेमी लेखक को करना चाहिए।

अमरकान्त का लेखन याद दिलाता है कि अपने समय की सत्ता से सवाल करना किसी भी लेखक का प्राथमिक कर्त्तव्य है। वे इन सवालों को रचनाओं में अनुस्यूत कर देते हैं और भूख, निर्धनता, गैर बराबरी, हिंसा, युवाओं की लाचारी जैसे अनेक सवाल स्थाई रूप से सबसे जवाब मांगते हैं। इस लिहाज से वे प्रेमचंद ही नहीं, भारतीय साहित्य की महान परंपरा की याद दिलाते हैं जिसमें तुलसीदास रामराज्य और रैदास बेगमपुर की कल्पना कर गए हैं। उनके उपन्यास भी साधारण मनुष्यता के असाधारण स्वप्नशीलता के उदाहरण हैं। बलिया में 1942 में भारत छोडो आंदोलन के दौरान हुई क्रांति का भव्य चित्र उन्होंने अपने उपन्यास 'इन्हीं हथियारों से' में प्रस्तुत कर दिया है। इसी उपन्यास में एक जगह आया है, 'हमारे देश में जहां अनेक धर्म और जातियां हैं, कैसी सरकार होगी? नस्लवादी राष्ट्रीयता यहां के लिए उपयुक्त होगी या धार्मिक राष्ट्रीयता? अथवा ऐसा जनतंत्र जिसमें सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार प्राप्त हों और शोषित-गरीबों की उन्नति पर ध्यान दिया जाता हो?' फिर एक और स्थान पर अमरकान्त एक पात्र के हवाले से कहते हैं, ''देखिए, आधुनिक बनिए। इसका मतलब दूसरों की नकल नहीं, अपने देश की प्राचीन सड़ी-गली, अप्रासंगिक एवं बेकाम चीजों की भी नहीं। इसका अर्थ है अपने इतिहास, संस्कृति और समाज से सबक लेते हुए अपने अंदर और दूसरों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और नई चुनौतियों का नए संकल्पों के साथ सामना करना।' उनके अन्य छोटे उपन्यास भी उत्तर भारत के जनजीवन की अनेक व्याधियों और यहां के लोगों की चित्तदशाओं का बयान हैं। स्त्रियों की दुर्दशा उन्हें बहुत विचलित करती है और उनका समूचा कथा साहित्य सबल स्त्री व्यक्तित्व की कामना करता है। ■

**अमरकान्त का लेखन याद दिलाता है कि अपने समय की सत्ता से सवाल करना किसी भी लेखक का प्राथमिक कर्त्तव्य है। वह इन सवालों को रचनाओं में पिरो देते हैं और भूख, निर्धनता, गैर बराबरी, हिंसा, युवाओं की लाचारी जैसे अनेक सवाल स्थायी रूप से सबसे जवाब मांगते हैं**

## इन्हीं हथियारों से बदलेगी दुनिया

''हमारे देश में जहां अनेक धर्म और जातियां हैं, कैसी सरकार होगी? नस्लवादी राष्ट्रीयता यहां के लिए उपयुक्त होगी या धार्मिक राष्ट्रीयता? अथवा ऐसा जनतंत्र जिसमें सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार प्राप्त हों और शोषित-गरीबों की उन्नति पर ध्यान दिया जाता हो?''

***

''हम ऐसा जनतंत्र चाहते हैं जिसमें सभी परिश्रम करें और एक-दूसरे की स्वतंत्रता, एक-दूसरे के विकास के लिए कार्य करें''

***

''देखिए, आधुनिक बनिए। इसका मतलब दूसरों की नकल नहीं, अपने देश की प्राचीन सड़ी-गली, अप्रासंगिक एवं बेकाम चीजों की भी नहीं। इसका अर्थ है अपने इतिहास, संस्कृति और समाज से सबक लेते हुए अपने अंदर और दूसरों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और नई चुनौतियों का नए संकल्पों के साथ सामना करना''

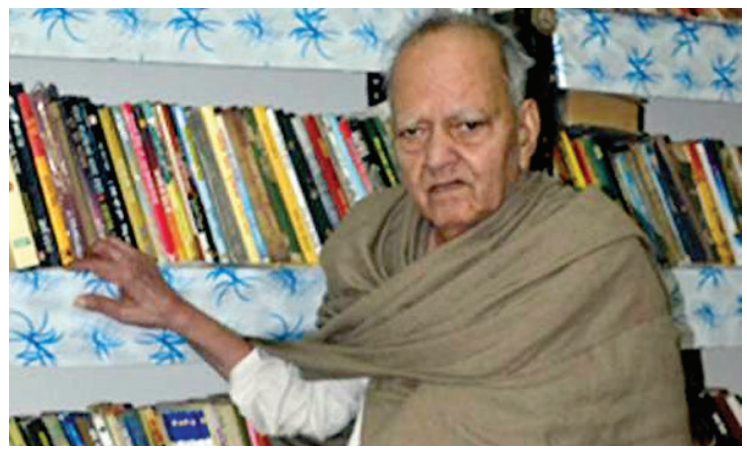

***

''अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग कोई नई चीज नहीं है। गांधीजी ने जनता से जुड़कर जनता के इतिहास से यह हासिल किया है। युगों से भयंकर हथियारों से लैस आततायियों और क्रूर अन्यायी शासकों ने जनता पर जुल्म ढाए हैं तो उसने अहिंसा, असहयोग, स्वावलम्बन, एकता, सत्याग्रह आदि इन्हीं हथियारों से उनका मुकाबला किया है''

('इन्हीं हथियारों से' उपन्यास में अमरकान्त)

Published Date 29 June, 2025 (Sunday), Posted at LPC Delhi RMS, Delhi-06, Posting Days Friday and Saturday

# गर आए कयामत तो ढेला थैच दे राहत

## मनोविकार की शिकार 'तिकड़ी' की वजह से परमाणु हमले का खतरा सिर पर है। वक्त रहते महफूज ठिकाना खोजना बुरा खयाल नहीं

अभय शुक्ला

चाहे आप नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर यकीन करें या नहीं, संदेह नहीं कि इंसानों के लिए यह समय बेहद खतरनाक है। ऐसे हालात की वजह है मनोविकार की शिकार अहंकार में डूबी वह तिकड़ी जिसके झूठ में पगे एक-एक ट्वीट इंसानों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचाते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में ड्रोन और रॉकेट ऐसे बरस रहे हैं जैसे विजय दिवस परेड में हवा में उड़ते कागज के जहाज। पश्चिम एशिया पर हाइपरसोनिक मिसाइलें और आईसीबीएम की बौछार उतनी ही आम बात हो गई है, जितनी अंबानी की शादी में रोलेक्स घड़ियां पहने मेहमान। पलटकर देश का रुख करें तो यही लगता है कि कोई नहीं जानता कि 'विश्वगुरु' की रगों का 'सिंदूर' कब संवर्द्धित यूरेनियम से बदल जाए और हम पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर बैठें और इसके जवाब में चीन भी हम पर परमाणु हथियार चला दे!

बेशक उत्तर भारत का मौजूदा तापमान गरम है। निकट भविष्य में सर्दी का कोई संकेत नहीं। लेकिन वह वक्त सिर पर टंग गया है जब हम 'नाभिकीय शीतकाल' में जान बचाने के लिए महफूज जगह की तलाश शुरू कर दें। डॉनल्ड ट्रंप के पास वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों में भूमिगत ठिकाने हो सकते हैं और मोदी के लिए सुरक्षित जगह केदारनाथ गुफा (कैमरे की चकाचौंध के बीच या फिर उसके बिना भी) हो सकती है, लेकिन यहां (हिमाचल के मेरे गांव) पुरानीकोटी में न तो बंकर हैं और न गुफाएं। यहां तो बस दिल्ली के वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किए गए घर हैं जो परमाणु हमले की तो बात ही छोड़ दीजिए, कंगना रनौत के झन-पटक को भी झेलने की स्थिति में नहीं। इसलिए मैं अपने तेजी से कमजोर होते दिमाग को सरपट दौड़ाकर एक सुरक्षित जगह की खोज में जुट गया जहां अपने परिवार और कुत्ते के साथ सिर छिपा सकूं, और मुझे लगता है कि मुझे वह जगह मिल गई है!

**दिलकश** कुल्लू जिले की सैंज घाटी स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के ढेला थैच कैंप के लिए ट्रैक पर जाता दल और लुप्तप्राय पश्चिमी ट्रैगोपैन (इनसेट) जिसे यहां आसानी से देखा जा सकता है।

वह जगह है ढेला थैच। (थैच घास का एक मैदान या घने जंगलों से घिरा मैदान होता है जो चरवाहों, गुज्जरों और ट्रेकर्स के लिए पारंपरिक रूप से कैंपिंग साइट होता है)। ढेला थैच कुल्लू जिले के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (जीएचएनपी) में है जो सैंज घाटी में नेउली में निकटतम सड़क से 35 किलोमीटर दूर, 12 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए दो दिनों की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है और यकीन करें, एक बार वहां पहुंचने के बाद लौटने की इच्छा नहीं होती। हालांकि मैं इस इच्छा को काबू करने में सफल रहा। मैं तीन बार वहां ट्रैक पर गया। कैंप किया। मैंने जिन मनोरम जगहों को देखा है, उनमें इसे ईडन (बाइबिल में वर्णित आनंद और पूर्णता का प्रतीक) के सबसे करीब पाया है। अगर वड्र्सवर्थ यहां आए होते तो इससे पहले कि आप कह पाते- 'माई हार्ट लीप्स अप' (वड्र्सवर्थ की एक कविता का शीर्षक), वह पूरी-पूरी एक नहीं, कई कविताएं लिख डालते!

ढेला करीब दो एकड़ में फैला हल्की ढलान वाला घास का मैदान है। यह कुल्लू के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में सैंज और तीर्थन घाटियों को अलग करने वाली रिज लाइन के ठीक नीचे है। एक ओर ओक और देवदार के पेड़ तो दूसरी ओर छोटे बुरांश और पहाड़ी बांस के घने जंगल। साथ ही पानी की जरूरत पूरी करता पतला नाला। कुल मिलाकर कैंपिंग के लिए एक आदर्श जगह! कैंपिंग साइट बौने बुरांश और खुशबू बिखेरते हपुषा के विशाल घने जंगल से घिरी है। सूर्यास्त के समय यहां मोनाल या हिमालयी मोर और दुर्लभ पश्चिमी ट्रैगोपैन या जुज्जु राना भोजन की तलाश में करलव करते बड़े आराम से दिख जाते हैं।

वन विभाग ने मैदान के ऊपरी किनारे पर सर्दियों में इस्तेमाल के काबिल लकड़ी की एक झोपड़ी बना रखी है (12 हजार फुट की ऊंचाई पर ढेला में बहुत अधिक बर्फ गिरती है)- साल के बाकी समय तो घाटी में कहीं भी टेंट लगाया जा सकता है। ऊंचाई, तरह-तरह की वनस्पतियां, खुला घसियाला मैदान और विकास के नक्शे पर अछूता रह जाना इसे हिमाचल की दो सबसे शानदार तीतर प्रजातियों- मोनाल और लुप्तप्राय पश्चिमी ट्रैगोपैन (जुज्जू राणा- शाब्दिक अर्थ पक्षियों का राजा) के लिए आदर्श रहवास बनाती हैं और इन दोनों को यहां देखा जाना एक आम बात है।

इसके नीचे की चट्टानें 'घोरल' (पहाड़ी बकरी) का घर हैं, जिन्हें सुबह की धूप सेंकते देखा जा सकता है। यहां से जीएचएनपी का नजारा अद्भुत है। उत्तर में 16 हजार फुट ऊंची भव्य खंडेधर श्रृंखला, उत्तर-पश्चिम में उससे भी ऊंची पिन पर्वत श्रृंखला, दक्षिण-पूर्व में तीर्थन पर्वत श्रृंखला और उसके पार से झांकती वह पर्वत श्रृंखला जिस पर श्रीखंड महादेव का पवित्र शिखर स्थित है। फिर, रंग-बिरंगे झंडों से पटा रिज के चोटी पर स्थित छोटा-सा धार्मिक स्थल 'जोगनी'। ध्यान लगाने, दुर्लभ पक्षियों को निहारने या फिर धूप सेंकते हुए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए बिल्कुल आदर्श!

ढेला ऐसी जगह नहीं जहां आप (विनाश के अलावा) कुछ कर सकते हैं; यह ईश्वर और प्रकृति की परम रचना है जो आपको सरल-सहज, नैसर्गिक सुंदरता और तकनीक, भौतिकवाद और मानवीय महत्वाकांक्षाओं से परे जीवन की लय में खो जाने का न्योता देती है। सुबह-शाम पक्षियों की चहचहाट सुनें। नहीं-नहीं यह आपके लिए नहीं, बल्कि एक और दिन के स्वागत की खुशी के लिए है! हर सुबह चमत्कृत होकर उगते सूरज को देखें और महसूस करें कि उसकी गर्मी प्रकृति के असंख्य जीवों को जीवन दे रही है, अपनी अंजुरी में पतले से झरने के बर्फीले पानी को भरकर उसे पीएं, कौतूहल के साथ 75 डिग्री की ढलान पर चरते घोरल को देखें, ऊपर पन्ना सरीखे नीले आसमान में मंडराते लैमर्जियर (दाढ़ी वाला गिद्ध जो ऊंचाई से हड्डियों को सपाट चट्टान पर गिराता है ताकि उसकी मज्जा खा सके) को देखें, रात में सुलगते कैंप फायर के पास आराम से बैठें और सोचें कि पतंगे खुद को आग में क्यों झोंक देते हैं- उन्हें आग की चमक पसंद है या वे इससे डरते हैं? धेला में तमाम सवाल हैं और उनके जवाब भी। उमर खैय्याम की फारसी में लिखी रुबाई याद आती है:

*'गर दली दुश्मन बोदी च ते'बीरम*
*एक शरब व दो नान व यार दबीरम'*
*('अगर एक प्याला शराब हो, रोटी का एक टुकड़ा हो,*
*कविता की एक पुस्तक हो और तुम मेरे पास हो,*
*तो जंगल में भी यह स्वर्ग ही होगा')* ■

ट्रंप के पास वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों में भूमिगत ठिकाने हो सकते हैं और मोदी के लिए सुरक्षित जगह केदारनाथ गुफा हो सकती है, लेकिन पुरानीकोटी में न तो बंकर हैं और न गुफाएं। परमाणु हथियार क्या, हिमाचल का यह गांव तो कंगना की झन-पटक भी नहीं सह सकता

अभय शुक्ला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यह avayshukla.blogspot.com से लिए उनके लेख का संपादित रूप है।


# ADVERTISEMENT RATE CARD

w.e.f. 1 January 2024

NATIONAL HERALD ON SUNDAY संडे नवजीवन

The AJL Group has two weekly newspapers and three website portals in English, Hindi and Urdu

www.nationalheraldindia.com | www.navjivanindia.com | www.qaumiawaz.com

Commercial Display ( w.e.f 1st Jan 2024)

| Category of Advertisements (C/BW) | National Herald on Sunday (National Edition) | (Mumbai) | Sunday Navjivan (National Edition) |
|---|---|---|---|
| Full Page (1650 sq.cm) | Rs 10 Lakh | Rs 8 Lakh | Rs 10 Lakh |
| Half Page (800 sq. cm) | Rs 6 Lakh | Rs 5 Lakh | Rs 6 Lakh |
| Quarter Page (400 sq. cm) | Rs 4 Lakh | Rs 3 Lakh | Rs 4 Lakh |
| < Quarter Page (400 sq. cm) | Rs 1515 per sq. cm | | |

| PAGE PREMIUM | Display Ads BW/Color | Political Ads BW/Color |
|---|---|---|
| Front page | 100% Surcharge | 200% Surcharge |
| page (3 & back) | 25% Surcharge | 100% Surcharge |
| Specified page | 50% Surcharge | 50% Surcharge |

*Advance payment is needed for all political advertisements.

**Classified for festival greetings and anniversary**
Full page @ Rs 1,00,000 | Half Page @ 60,000
< 240 sq. cm @ Rs 175 per sq. cm

**State Govt Advertisements/ C/BW**
@ Rs 525 per sq. cm

**The Associated Journals Limited**
Herald House, 5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110002
Phone: 011-47636300 - 313
Whatsapp No: 9650400932
Email: advt@nationalheraldindia.com

**Online Remittance/Bank Beneficiary Details:**
Name: **Associated Journals Limited**
Bank Name: **Canara Bank**
Branch Name: **I P Estate, New Delhi-110002**
C/A No.: **90171010003955;** IFSC Code: **CNRB0019017**
GST No.: **27AAECA1180A1ZB ;** PAN No.: **AAECA1180A**

NOTE: Cheque / DD should be drawn in favor of "Associated Journals Limited" and sent to Herald House, 5-A Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002.

# General Terms and Conditions

w.e.f. 1 January 2024

National Herald on Sunday (Delhi & Mumbai) and Sunday Navjivan

1. All advertisements are published in Edition(s) of the paper and charges are payable strictly in advance of publication by Bank Draft or Bank Transfer (RTGS) and /or cheques only except in the case of advertising agencies accredited to INS.

2. Advertisements are accepted for publication on top of advertisements positions on an additional charge of 25%. No advertisement is however published on top of news-matter.Top of column position cannot be guaranteed even on payment of additional charge of 25%.

3. Extra charges for top of column position are calculated on the total amount payable inclusive of amount payable for specified pages.

4. Every reasonable effort is made to publish an advertisement on the date(s) specified by an advertiser. The Management however reserves the right to vary the date or the scheduled date(s) of publication, with or without notice to the advertiser, owing to the exigencies of availability of spaces.

5. The management reserves the right to refuse, suspend or stop, in its discretion, publication of any advertisement without assigning any reasons.

6. While every endeavour will be made by the Management to avoid publication of competitive advertisements in close proximity to one another, no guarantee can be given in this respect nor will the claims be entertained for free insertions in the event of announcements of rival product appearing on the same page.

7. The placing of an order by an Advertiser/Advertising Agency constitutes a warranty by the Advertiser/Advertising Agency to the Associate Joumals Limited Management that the Advertiser/ Advertising Agency has secured the necessary authority and permission in respect of the use in the advertisement or advertisements of pictorial representation of (or purporting to be of) living persons and all references to words attributing to living persons.

8. The advertisements will be charged at the rate applicable on the day of publication of the advertisement irrespective of the date of booking, date of release order and whether the advertisement is part of any package/scheme.

9. Standing instructions are accepted over Whatsapp or email. However verbal instructions must be clear and specific. Quoting reference of the previous release order and/or new scheduled dates of insertions in respect of which the instructions are given. These instructions should be given afresh either through Whatsapp/email and/or Landline phone.

10 Booking of space for premium positions in all The Associated Journals Limited publications will be confirmed only upon receipt of original releaseorder. Fax/Scanned copies, Emails will be entertained for the same.

11. "Reader" advertisements are accepted but will be distinguished from 'news matter' by a rule around the advertisement matter and expression 'advt' will be added at bottom.

12. Solus/Semi Solus positions cannot be guaranteed on the front page.

13. Cancellation charges @20% of the total cost of the front/Full page advertisement shall be levied if a cancellation of booking is made two days before the scheduled date of publication. Cancellation charges @35% of the total cost of the full front-page advertisement shall be levied if the cancellation of a booking of front/full page advertisement is made one day before the scheduled date of the publication.

14. In the event of printing mistake, omission or non-publication of advertisement, the advertising agencies shall have to furnish the instructionson behalf of their client for republication. In the event of a dispute the liability of Management shall be restricted to the amount received against sale of spaces for the advertisement received. All disputes /claims regarding advertisement /complaints must be made within a period of one month of publication date after which no claim will be entertained.

15. The Management shall not be responsible for any loss or damage caused by an error or inaccuracy in the printing of/or omission in inserting advertisements.

16. In case of dispute, the agency shall not be entitled to invoke any condition suggestive of existence of an arbitration agreement unless specifically agreed to by the Management.

17. No deduction is allowed from bills raised against publication of advertisement(s) on account of any defective insertion(s). Any claims in these respects, if admitted, will be met by publishing a corrigendum/ free insertion or the like, depending upon the merits of the claim vis-a-vis the error in publishing the advertisement(s) or other materials. Claims for refund or for compensation, if admitted, shall be restricted to the charges for advertisement received by Management. The decision of the management shall be final in this regard.

18. The advertisements released by Government/Semi Government/ Undertakings/Autonomous body are published in classified display column only at commercial rates irrespective of the number of words.

19. The advertising agencies releasing an advertisement on behalf of its client shall be deemed to have undertaken to keep the management indemnified in respect of costs, damages or other charges incurred by the Management as a result of any legal action or threatened legal action arising from and in relation to publication of any advertisement published in accordance with the release order and the copy of instructions supplied by the agency.

20. The agency shall bring to the notice of its clients these General Terms and it shall not be open to any of its clients to plead/claim or aver ignorance of these General Terms which apply to every transaction of sale of space in particular issue(s) of any of publications of The Associated Joumals Limited.

21. No agency commission is payable on the on the classified advertisements chargeable at DAVP rates.

22. Fraction of centimetre in excess of the scheduled size shall be charged as full centimetre if the advertisement exceeds the scheduled size. If the material supplied is shorter than the scheduled size, the advertisement will be charged for the size scheduled and not for theactual space occupied or consumed by the advertisement on the basis of the short size material so supplied.

23. The Management shall not be bound by notice of stoporders, cancellations, preponements/postponements or alterations/deletions/ additions in the material(s) of advertisement(s) booked for publication in special or specified position if received less than one week prior to dates of insertion. For ordinary advertisement, the stoppage or not of cancellation must reach at least four days before the scheduled date of publication of advertisement.

24. The Management reserves the rights to revise the rates and terms and conditions without any notice.

25. Every Advertiser/Advertising Agency acknowledges having read and accepted these Terms and Conditions.

26. Courts only in New Delhi, shall have the jurisdiction to entertain and decide all disputes and claims, arising out of publication of any advertisement in the Associate Journals limited publications.

27. The Management shall be at liberty to refuse to carry advertisements/ adjust amounts paid for subsequent ads against pre-existing liabilities, even without carrying such subsequent advertisement.

28. Advertising party hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless AJL, it's directors, officers, shareholders and agents against any and all third party claims arising out of or in connection with the content or placement of the advertisement, and to the fullest extent.

29. In no event shall AJL be liable hereunder for any indirect, incidental, special, consequential, punitive or exemplary damages or losses in connection with these terms even if advised in advance of the possibility of arising of such liability, damages or losses.

30. In no event shall AJL's aggregate liability exceed Rs. 10,000 to any advertising party.